https://www.facebook.com/Kamal.Sandesh/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल थी आजाद हिंद सरकार

वर्ष-13, अंक-21 01-15 नवम्बर, 2018 (पाक्षिक) ₹20

भाजपा करती है विकास की राजनीति

यूपीए सरकार में बांटे गए अंधाधुंध कर्ज से हुई बैंकिंग व्यवस्था की हालत खराब

भारत का नव-तीर्थ - स्टैच्यू ऑफ यूनिटी

जनता से किए गए वादों को पूरा करने में असफल रही है तेलंगाना सरकार

जबलपुर (मध्य प्रदेश) में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में अभिवादन स्वीकार करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह व अन्य नेतागण

बिलासपुर (छत्तीसगढ़) में बिलासा देवी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

रायपुर (छत्तीसगढ़) में बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

आइजोल (मिजोरम) में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में अभिवादन स्वीकार करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री श्री राम माधव व अन्य

गुवाहाटी (असम) में मां कामाख्या देवी शक्तिपीठ पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल, असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल व अन्य

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com

वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 छत्तीसगढ़ की पीडीएस योजना को देश के कई अन्य राज्य अपना रहे हैं : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 12 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर और बिलासपुर में क्रमशः अंबिकापुर और बिलासपुर संभाग के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया...

वैचारिकी

सांस्कृतिक अधिष्ठान 14

श्रद्धांजलि

भोला सिंह 16

लेख

यूपीए सरकार में बांटे गए अंधाधुंध कर्ज से हुई बैंकिंग व्यवस्था की... 18
भारत का नव-तीर्थ - स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 20

अन्य

भाजपा ने जम्मू नगर निगम चुनाव में लहराया परचम 10
दिल्ली में वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली की शुरुआत 13
साईं से मिलती है जनसेवा की प्रेरणाः नरेन्द्र मोदी 17
मानवाधिकार की रक्षा हमारी संस्कृति का बेहद अहम हिस्सा रहा है... 21
देश में प्रमुख फसलों के उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी 75 फीसदी 22
ऊर्जा सुरक्षा, किफायती ऊर्जा एवं ऊर्जा निरंतरता की ओर तेजी से ... 23
देश की तरक्की के लिए जरूरी है सरकारी खजाने की सेहत में तेजी... 24
'मिजोरम की जनता बदलाव चाहती है' 25
'जनता से किए गए वादों को पूरा करने में असफल रही है तेलंगाना... 26
राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल थी आजाद हिंद सरकारः प्रधानमंत्री 28
'भाजपा सरकार ने तुष्टिकरण की राजनीति की जगह पॉलिटिक्स ऑफ़... 29
प्रधानमंत्री को मिला सियोल शांति पुरस्कार 30
मोदी सरकार 'शून्य भुखमरी' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए... 32
'मोदी सरकार महिला सशक्तीकरण को समर्पित' 33

स्थायी स्तंभ

सोशल मीडिया से 04
व्यंग्य चित्र 04

08 'विकास के सभी मापदंडों पर खरा उतर रही है मध्य प्रदेश सरकार'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 14 अक्टूबर को गुप्ता ग्राउंड, होशंगाबाद में भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग...

09 'भाजपा सरकार ने दिया महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 15 अक्टूबर को बी.टी.आई....

11 प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पुलिस स्मारक राष्ट्र को समर्पित

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21 अक्टूबर को पुलिस स्मारक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय...

12 तेल उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच साझेदारी जरूरी: नरेन्द्र मोदी

कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के उछाल के बीच प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तेल...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

यह हमारी सरकार के लिए सम्मान का विषय है कि हमने सेनाओं में कार्य कर रही महिलाओं समेत सशस्त्र सेनाओं के कल्याण हेतु अनेक कदम उठाए हैं।

@AmitShah

भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही राजनीति में पारदर्शिता व शुचिता की पुरुजोर समर्थक रही है और केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में एक पारदर्शी सरकार देकर पार्टी की सोच को चरितार्थ करके दिखाया है।

@Ramlal

जनसंघ स्थापना दिवस (21 अक्टूबर) पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पं. दीनदयाल जी को सादर नमन। जनसंघ के रूप में प्रारम्भ यात्रा कार्यकर्ताओं की कर्मठता के फलस्वरूप भाजपा जैसे वटवृक्ष के रूप में चरितार्थ है। सभी समर्पित कार्यकर्ता राष्ट्रहित में कटिबद्धता से कार्य करके इस परम्परा को आगे ले जा रहे हैं।

facebook

राज्य की भाजपा सरकार श्रमवीरों की सरकार है। प्रदेश के 28 लाख पंजीकृत श्रमिकों का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कराया जाएगा। आश्रित परिजनों को दुर्घटना में 4 लाख व सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए तक की बीमा राशि मिलेगी।

— डॉ. रमन सिंह

हिमालय को हमारी नहीं, बल्कि हमें हिमालय की जरूरत है। हिमालय प्रत्यक्ष तौर पर करोड़ों लोगों के जीवन व जीविका को प्रभावित करता है, इसलिए हिमालय संरक्षण के लिए समेकित प्रयासों की जरूरत है।

— त्रिवेंद्र सिंह रावत

एनडीए सरकार बेनामी सम्पत्ति निवारण कानून को इतना मजबूत बना दिया है कि इस मामले में दोषी पाए जाने पर 7 साल के कारावास की सजा, सम्पत्ति के बाजार मूल्य का 25 फीसद जुर्माना और इसके साथ ही 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। लालू प्रसाद ने बिहार का विकास तो ठप किया ही, सम्पत्ति की लिप्सा में अपने परिवार की दूसरी पीढ़ी का भविष्य भी अंधकारमय बना दिया।

— सुशील कुमार मोदी

व्यंग्य चित्र

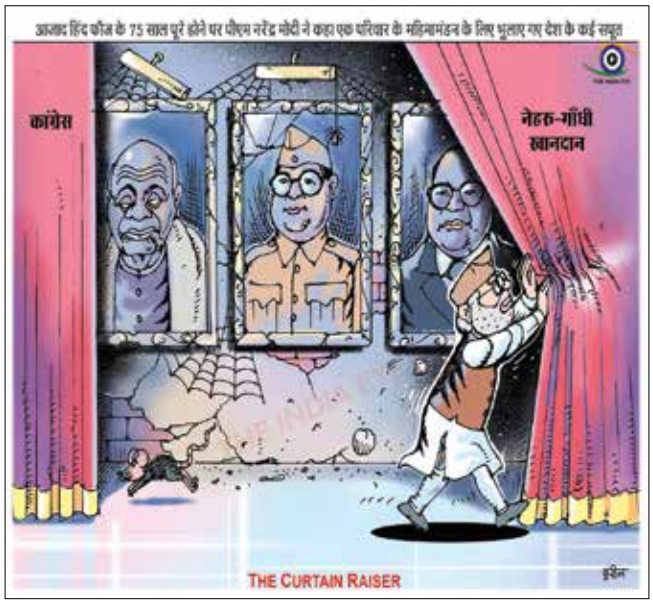

सभार : सोशल मीडिया

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव

भारी जीत की ओर अग्रसर भाजपा

पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। नवंबर एवं दिसंबर माह में विभिन्न चरणों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एवं मिजोरम में लोग अपने प्रदेश के सरकारों को चुनने के लिए मतदान करेंगे। वोटों की गिनती 11 दिसंबर को होगी। जो भी राजनीतिक दल इन चुनावों में अपनी गंभीर दावेदारी कर रहे हैं, अब जनता के बीच जा रहे हैं। इन राज्यों में चुनाव अभियान शुरू हो चुका है और जनता तक सभी दल प्रचार के लिए जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में पिछले तीन चुनावों से जनता लगातार भाजपा सरकार चुन रही है। राजस्थान में भी पिछले चुनाव में भाजपा ने शानदार जीत हासिल की थी। तेलंगाना जहां विधानसभा चुनाव समय से पहले कराये जा रहे हैं, वहां तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार है। मिजोरम में वर्तमान में कांग्रेस सरकार का शासन है।

भाजपा शासन में मध्य प्रदेश में जबरदस्त विकास हुआ है। यह एक ऐसा राज्य है जो कभी 'बीमारू' राज्यों की श्रेणी में था, परन्तु भाजपा सरकार में हर क्षेत्र में इसने अद्भुत प्रगति की है। कृषि विकास दर ने किसी को भी अचंभे में डालने की हद तक छलांग लगाई है और कृषि क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। इसी प्रकार से प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने भी हर क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज की है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों का दिल जीता है और यही कारण है कि प्रदेश की जनता बार–बार उनमें अपना विश्वास प्रकट कर रही है।

गरीब से गरीब के प्रति समर्पित भाजपा सरकार का परिणाम यह है कि आज पूरे देश में अनेक अभिनव योजनाओं के माध्यम से किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, महिला एवं युवा के जीवन में व्यापक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। भारत का राजनैतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है और लोग भाजपा की ओर आशा एवं आकांक्षा से देख रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा भारी जीत की ओर बढ़ रही है।

इसी प्रकार मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने विकास की नई गाथा लिखी है। मध्य प्रदेश से अलग हो छत्तीसगढ़ बनने के बाद यह आदिवासी बहुल प्रदेश आज देश के अन्य राज्यों से कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की ही दूरदर्शिता थी कि भाजपा के छोटे राज्यों को समर्थन के सिद्धांत के आधार पर उन्होंने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था और उसका सुफल आज सबके सामने है। इसकी विकास-गाथा ने न केवल नक्सलवाद पर लगाम लगाई है, बल्कि प्रदेश का औद्योगिक विकास भी तेज हुआ है।

राजस्थान में कांग्रेस कुशासन के एक दौर के बाद भाजपा को जनता ने पिछले चुनाव में भारी समर्थन दिया। भाजपा के शासन में आने के बाद राजस्थान पुनः एक बार विकास एवं सुशासन की राह पर चल पड़ा है। बड़ी संख्या में कल्याणकारी योजनाओं से लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन हो रहा है। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में प्रदेश चहुंमुखी विकास के पथ पर अग्रसर है।

उत्तर–पूर्व में जनता भाजपा एवं नेडा के पक्ष में मतदान कर रही है। देश के अन्य भागों की तरह ही उत्तर–पूर्व की भी जनता कांग्रेस पर से अपना विश्वास खो चुकी है। मिजोरम में भी जनता परिवर्तन की राह देख रही है और भाजपा का यहां मजबूती से उभरना तय है। तेलंगाना राष्ट्र समिति की मुश्किलें प्रदेश में बढ़ी हैं और यही कारण है कि उसने वहां समय से पूर्व चुनाव का निर्णय लिया। तेलंगाना में भी भाजपा दृढ़ता से आगे बढ़ेगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व में भाजपा का जनसमर्थन निरंतर बढ़ता जा रहा है और लोग हर जगह भाजपा पर बारंबार विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। गरीब से गरीब के प्रति समर्पित भाजपा सरकार का परिणाम यह है कि आज पूरे देश में अनेक अभिनव योजनाओं के माध्यम से किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, महिला एवं युवा के जीवन में व्यापक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के दूरदर्शी एवं कड़ी मेहनत वाले नेतृत्व में करोड़ों कार्यकर्ता आज मां भारती की सेवा में निरंतर समर्पित होने की प्रेरणा पा रहे हैं। भारत का राजनैतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है और लोग भाजपा की ओर आशा एवं आकांक्षा से देख रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा भारी जीत की ओर बढ़ रही है।

shivshakti@kamalsandesh.org

छत्तीसगढ़ की पीडीएस योजना को देश के कई अन्य राज्य अपना रहे हैं: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 12 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर और बिलासपुर में क्रमशः अंबिकापुर और बिलासपुर संभाग के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं से पुनः राज्य में दो तिहाई से अभी अधिक बहुमत के साथ भाजपा की रमण सिंह सरकार बनाने का आह्वान करते हुए छत्तीसगढ़ की अनदेखी करने के लिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर करारा हमला किया।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की रमण सिंह सरकार ने तेंदुपत्ता बीनने वालों के पैर में चरण पादुका पहनाने का कार्य किया है। तेंदुपत्ता इकठ्ठा करने वाले मजदूरों के मानांक को बढ़ाने का कार्य किया गया है और वनवासी बंधुओं को लाखों हेक्टेयर की भूमि आवंटित कर उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि गरीबों को नाम मात्र के मूल्य पर चावल और गेहूं वितरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की इस प्रसिद्ध और सफल पीडीएस योजना को देश के कई अन्य राज्य अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि रमण सिंह सरकार ने समर्थन मूल्य से भी 200 रुपये अधिक के मूल्य पर राज्य की जनता से धान की खरीदी कर किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त अन्य फसलों पर भी किसानों को बोनस दिया जा रहा है और समर्थन मूल्य पर वन उत्पादों की भी खरीद की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में छत्तीसगढ़ अशिक्षा, अंधेरे और पिछड़ेपन का हब माना जाता था, लेकिन आज छत्तीसगढ़ शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, उद्योग और पावर का हब बना है। उन्होंने कहा कि एक लाख से तीन लाख की आबादी वाले शहर के स्वच्छता सर्वेक्षण के बेस्ट इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज सेगमेंट में अंबिकापुर को देश में पहला स्थान मिला है जो राज्य की बदलती तस्वीर को पेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में छत्तीसगढ़ का विकास आश्चर्यचकित कर देने वाला है। उन्होंने कहा कि राज्य में सातवें वेतनमान को लागू कर कर्मचारियों के हितों की रक्षा की गई है। काफी कम कीमत पर किसानों को सोलर पम्प उपलब्ध कराया जा रहा है, गरीबों को 40 यूनिट निःशुल्क बिजली मुहैया कराई जा रही है। गरीबों को एक किलो रुपये चावल और मुफ्त में नमक उपलब्ध कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, राज्य की भाजपा सरकार ने मनरेगा में श्रमिकों को एक वर्ष में पचास अतिरिक्त दिनों का रोजगार देने का भी कल्याणकारी निर्णय लिया है।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि 13वें वित्त आयोग में कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए महज 48,088 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की थी, जबकि मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग में राज्य के विकास के लिए लगभग 1,37,927 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है जो यूपीए सरकार की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है। इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को अलग से लगभग 18 हजार करोड़ रुपये की राशि दी गई है। खदानों के पारदर्शी नीलामी से छत्तीसगढ़ को लगभग 1,15,000 करोड़ रुपये की आय हुई है। उन्होंने कहा कि मुद्रा बैंक योजना से राज्य के 10 लाख से अधिक युवा लाभान्वित हुए हैं। साथ ही, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत राज्य की लगभग

36 लाख गरीब महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि राहुल गांधी बताएं कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के 10 वर्षों में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या-क्या काम किये गए?

एनआरसी के मुद्दे पर कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पूरे देश की जनता घुसपैठिये को चुन-चुन कर बाहर करने के पक्ष में है, लेकिन राहुल गांधी एंड कंपनी घुसपैठियों के पक्ष में खड़ी हो गई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एंड कंपनी को घुसपैठियों के मानवाधिकार की चिंता तो है, लेकिन देश के नागरिकों के मानवाधिकार की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि देश को आतंकवाद, घुसपैठ और नक्सलवाद से मुक्त करना भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि राहुल गांधी, आप कितना भी करो, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की दाल गलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार आई तो फिर से भ्रष्टाचारियों के भरोसे प्रदेश को छोड़ना पड़ेगा। ■

'छत्तीसगढ़ में बुनियादी सुविधाओं में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 13 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और रायपुर में जगदलपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि जनता से मिल रहे अपार प्रेम और समर्थन से यह निश्चित है कि इस बार 65 सीटों पर विजय के साथ भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है।

राज्य की जनता को भाजपा सरकार बनने से पहले छत्तीसगढ़ की स्थिति की याद दिलाते हुए श्री शाह ने कहा कि जब राज्य में कांग्रेस की अजित जोगी सरकार थी, तब छत्तीसगढ़ में न तो बिजली थी, न पानी था, न सड़क थी और न ही स्वास्थ्य की सुविधाएं ही थीं। उस वक्त नक्सलवाद को राज्य में फलने-फूलने दिया गया और भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। ऐसी विषम परिस्थिति में छत्तीसगढ़ की जनता ने शरीर की बीमारी दूर करने वाले एक डॉक्टर डॉ. रमण सिंह को राज्य की बीमारी दूर करने की जिम्मेदारी सौंपने का काम किया। उन्होंने कहा कि उसके बाद से छत्तीसगढ़ में बुनियादी सुविधाओं में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ। हर गांव में बिजली, सड़क, स्कूल और पीने योग्य पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हर अंचल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया है और सबसे बड़ा कार्य नक्सलवाद की समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने का किया गया है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के शासन के दौरान छत्तीसगढ़ का बजट केवल 9,270 करोड़ रुपये था, जबकि रमण सिंह सरकार ने राज्य का बजट लगभग 10 गुना बढ़ाकर 94,775 करोड़ रुपये किया है। कांग्रेस के समय राज्य की जीएसडीपी लगभग 38,000 करोड़ रुपये थी जबकि वर्तमान में यह बढ़कर लगभग 2,91,000 करोड़ रुपये हो गई है। कांग्रेस शासन के समय राज्य की प्रति व्यक्ति आय जहां केवल 13 हजार रुपये था, वहीं आज यह बढ़कर लगभग 92 हजार रुपये हो गई है। कांग्रेस सरकार में छत्तीसगढ़ में केवल 4,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, जबकि आज राज्य में 22,000 मेगावाट से अधिक विद्युत् उत्पादन हो रहा है। खाद्यान्न और फलों के उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई है। मत्स्य उत्पादन 1 लाख टन से बढ़कर 3.75 लाख टन हो गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार के शासन में छत्तीसगढ़ ने कांग्रेस सरकार की तुलना में कई गुना की वृद्धि न की हो।

श्री शाह ने कहा कि राहुल गांधी हमारी सरकार के कामकाज का हिसाब मांग रहे हैं, जबकि देश की 50 करोड़ गरीब जनता राहुल गांधी से कांग्रेस सरकार की चार पीढ़ियों के कामकाज का हिसाब मांग रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हर संभव कदम उठाये हैं। चाहे वह आदिवासियों के कल्याण के लिए हो, तेंदुपत्ता कर्मियों के कल्याण के लिए हो, गरीब नागरिकों के जीवन में उत्थान की योजनायें हो या फिर राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर को गति देने की योजना। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले चार सालों में 31 करोड़ से अधिक लोगों के जन-धन खाते खोले, साढ़े 5 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस सिलिंडर दिए, साढ़े सात करोड़ से अधिक करोड़ शौचालयों का निर्माण कराया, दो करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई, 18 करोड़ छोटे गरीब बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया एवं दो करोड़ घरों का निर्माण कराया है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जनता से वोट मांगने के पहले राहुल गांधी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी किसके नेतृत्व में

छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने जा रही है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की न तो कोई विचारधारा है, न नेता है, न नीयत और न ही नेतृत्व।

'अर्बन नक्सलियों' की गिरफ्तारी पर बोलते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी देश तोड़ने वाले को क्यों बचा रही है? कांग्रेस पार्टी माओवादी नक्सलियों के साथ है फिर देश की जनता के साथ? कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को भले ही देश की सुरक्षा की चिंता न हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भाजपा सरकार की हमेशा से देशद्रोहियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रही है और हमारा स्पष्ट मानना है कि ऐसे देशद्रोही लोगों की जगह जेल की सलाखों के पीछे ही है।

श्री शाह ने कहा कि राहुल गांधी को छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने का दिवास्वप्न आ रहा है, लेकिन 2014 से लेकर आज तक देश में हुए लगभग सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी का यही हश्र होने वाला है। ■

'विकास के सभी मापदंडों पर खरा उतर रही है मध्य प्रदेश सरकार'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 14 अक्टूबर को गुप्ता ग्राउंड, होशंगाबाद में भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग की 36 विधानसभाओं के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और मध्य प्रदेश से लगातार भेदभाव करने वाली कांग्रेस पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकने की जनता से अपील की।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी केंद्र में नेतृत्वविहीन है, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के नेतृत्व का अता-पता नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि राहुल गांधी, मध्य प्रदेश की जनता से वोट मांगने से पहले आप स्पष्ट करें कि आप किसके नेतृत्व में मध्य प्रदेश का विधान सभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य में राजा, महाराजा और उद्योगपति के सहारे चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि एक राजा, एक महाराजा और एक उद्योगपति को साथ लेकर जनादेश प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है।

श्री शाह ने कहा कि राहुल गांधी हमारी सरकार के कामकाज का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी की चार पीढ़ियों के सरकार का हिसाब मांग रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता यह भी जानना चाहती है कि केंद्र में 10 वर्षों तक चलने वाली कांग्रेस की सोनिया-मनमोहन सरकार ने मध्य प्रदेश के साथ घोर अन्याय क्यों किया? उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम जब भी चुनाव में जाते हैं तो हम जनता को अपने पल-पल और पाई-पाई का हिसाब देते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान 13वें वित्त आयोग में मध्य प्रदेश को विकास के लिए जहां केवल 1,34,190 करोड़ रुपये की राशि दी थी, वहीं मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग में प्रदेश के लिए लगभग 3,44,126 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय योजनाओं में मोदी सरकार ने अलग से मध्य प्रदेश को लगभग 57,000 करोड़ रुपये दिए हैं। साथ ही, मध्य प्रदेश को खनिज से लगभग 54,000 करोड़ रुपये अलग से प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता को ससम्मान उनका अधिकार देने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साढ़े चार साल में औसतन हर 15 दिन में एक नई योजना की शुरुआत की है और खुद मॉनिटरिंग कर इसका सुचारू रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया है।

श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस ने देश में 55 वर्षों से अधिक समय तक शासन किया, मध्य प्रदेश में भी वर्षों तक कांग्रेस की सरकारें रही। उन्होंने कहा कि जब मध्य प्रदेश में जनता ने कांग्रेस की श्रीमान बंटाधार सरकार की विदाई की तब राज्य की केवल 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि ही सिंचित थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्षों के शासनकाल में सिंचित भूमि का रकबा बढ़कर 40 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि इन 15 सालों में कांग्रेस सरकार की तुलना में विद्युत् उत्पादन 2,900 मेगावाट से बढ़कर 17,700 मेगावाट पहुंच गया है। 45 हजार किलोमीटर की सड़क बढ़कर 95

हजार किलोमीटर हो गई है, गेहूं का उत्पादन 49 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 219 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा है। धान का उत्पादन 17 लाख मीट्रिक टन से तीन गुने से भी अधिक बढ़कर 54 लाख मीट्रिक टन हो गया है। माध्यमिक पाठशालाएं 18 हजार से बढ़कर 30 हजार हो गई है और हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। आईटीआई संस्थानों की संख्या 222 से बढ़ कर लगभग 1,000 हो गई है और इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेजों की संख्या में भी कई गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय मध्य प्रदेश की कृषि विकास -3% के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई थी, जबकि शिवराज जी के शासनकाल में यह (+) 20% से भी ऊपर के अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई। ये आंकड़े दिखाते हैं कि जब एक सरकार समर्पण भाव से प्रदेश की भलाई के लिए एवं जनता के कल्याण के लिए काम करती है, तो किस प्रकार के परिणाम आते हैं। उन्होंने कहा कि विकास के सभी मापदंडों पर भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने कांग्रेस सरकार की तुलना में काफी बेहतर कार्य किया है। ■

'भाजपा सरकार ने दिया महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 15 अक्टूबर को बी.टी.आई. ग्राउंड, रीवा रोड, सतना में कमल शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला सम्मेलन और एस.ए.एफ. ग्राउंड, गुढ़ रोड, रीवा में शहडोल एवं रीवा संभाग के 7 जिलों के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया।

श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के मूल में कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा निहित है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नेताओं के आधार पर नहीं, कार्यकर्ताओं के आधार पर चुनाव जीतती है। उन्होंने कहा कि हमें इस विजय यात्रा को इसी तरह अनवरत जारी रखते हुए मध्य प्रदेश में हर बूथ में कमल खिलाने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ऐसी विजय होनी चाहिए जो पूरे हिन्दुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का झंडा शान से बुलंद करने की नींव बने, ताकि अगले 50 सालों तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कोई भी भाजपा को पराजित न कर पाए। "अबकी बार, 200 पार।"

श्री शाह ने कहा कि देश की मातृशक्ति ने दुनिया में भारतवर्ष के मान-सम्मान को बढ़ाने का कार्य किया है। केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किये गए कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण अभियान हो, गर्भवती महिलाओं को पोषण के लिए आर्थिक सहायता हो, लक्ष्मी लाडली योजना हो, हर क्षेत्र में केंद्र की मोदी सरकार एवं राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह सरकार में मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में भी काफी कमी आई है और साथ ही अब 26% की जगह 81% प्रसूति अस्पतालों में होती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की शिक्षा दर में भी काफी सुधार आया है। अब प्रदेश की 90% बालिकाएं विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं जबकि पहले केवल 45% लड़कियां ही स्कूल जा पाती थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के स्वरोजगार के लिए लाखों स्व-सहायता समूह कार्यरत है। उन्होंने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना तो पूरे देश में कहीं और नहीं है, जहां बालिकाओं के जन्म के साथ ही सरकार एक लाख रुपये का बांड जारी कर दिया जाता है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार ने 7.5 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कर महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। सभी स्कूलों में शौचालय निर्माण का कार्य शत-प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। लगभग 4 करोड़ से अधिक महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलिंडर देकर धुएं से मुक्ति दिलाई है। उन्होंने कहा कि दो करोड़ घरों में बिजली और दो करोड़ गरीब बहनों को पक्के घर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर सभी बैंकों को दलित, आदिवासी एवं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अलग से ऋण उपलब्ध कराने को कहा गया है। मुद्रा बैंक योजना के तहत देश के 12 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं जिसमें काफी संख्या में महिलायें हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की किसी भी सरकार में एक साथ 9 महिला मंत्री कभी नहीं रही। आज मातृशक्ति देश की विदेश मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय का जिम्मा संभाल रही है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में हिन्दुस्तान की मातृशक्ति का डंका बज रहा है।

ट्रिपल तलाक की चर्चा करते हुए श्री शाह ने कहा कि ट्रिपल तलाक मुस्लिम बहनों के लिए अभिशाप की तरह है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है, उसे मुस्लिम बहनों की पीड़ा का तनिक भी अहसास नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अध्यादेश लाकर मुस्लिम महिलाओं

को ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाने का कार्य किया है।

श्री शाह ने कहा कि आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता के पास दो विकल्प हैं - एक तरफ सालों तक गरीबी हटाओ का नारा लगाकर गरीबों को हटाने वाली कांग्रेस तो दूसरी तरफ बिना कोई नारा दिए दिन-रात एक कर गरीबों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों एवं महिलाओं के कल्याण के लिए काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नीति, नीयत और नेतृत्व विहीन पार्टी है जिसका न तो कोई सिद्धांत है और न ही कोई विचारधारा। उन्होंने कहा कि श्री शिवराज सिंह चौहान समृद्ध मध्य प्रदेश का संकल्प लेकर निकले हैं। राज्य की जनता उन्हें चौथी बार अपना आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करे। ■

भाजपा ने जम्मू नगर निगम चुनाव में लहराया परचम

कश्मीर में भी किया अच्छा प्रदर्शन

भाजपा ने जम्मू नगर निगम (जेएमसी) चुनाव में भारी जीत दर्ज की, साथ ही कश्मीर घाटी में भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए 100 वार्डों में जीत दर्ज की। यह स्थिति राज्य में चार चरणों में संपन्न स्थानीय नगर निकाय चुनावों में रही, जिसके परिणाम 20 अक्तूबर 2018 को घोषित किए गए।

जम्मू में कांग्रेस को इस चुनाव में भारी हानि का सामना करना पड़ा, जिसमें उसे 74 सदस्यीय सदन में केवल 14 सीटें ही मिल पाईं। जेएमसी में स्वतंत्र उम्मीदवारों को 18 सीटें मिलीं। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू नगर निगम की 75 सीटों में से 43 सीटें जीतीं, जो 2005 में हुए विगत नगर निकाय चुनावों की तुलना में उसे 18 सीटों का लाभ मिला। इससे पूर्व भाजपा के पास 25 सीटें थीं।

जम्मू की सात म्युनिसिपिल समितियों में भाजपा ने 11 सीटों के साथ अखनूर सीट जीती, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर विजयी रही। बिश्नाह में भाजपा सात निर्दलियों के मुकाबले छह सीटों पर विजयी रही। अर्निया में भाजपा ने सात सीटें, 5 निर्दलियों ने और एक पर कांग्रेस ने विजय प्राप्त की। आरएसपुरा में भाजपा 9 सीटें, निर्दलियों ने तीन और कांग्रेस ने एक सीट जीती। घमनहासन में भाजपा ने 2 सीटें जीतीं और कांग्रेस ने 2 और जूरियन में भाजपा ने दो सीटें जीतीं और कांग्रेस ने चार तथा निर्दलीय ने एक सीट पर विजय प्राप्त की।

कश्मीर घाटी में चुनाव अधिकारियों के अनुसार चुनावों में कश्मीर डिवीजन के 42 नगर निकायों के 178 वार्डों में निर्दलीय चुनाव जीतकर सबसे बड़े ग्रुप के रूप में उभरे, जिसमें लेह और कारगिल भी शामिल हैं। कांग्रेस को 157 वार्डों में विजय प्राप्त हुई, जबकि भाजपा ने घाटी में 100 वार्डों में विजय प्राप्त की। एनसी और पीडीपी ने चुनावों का बहिष्कार किया।

जबकि भाजपा 12 म्युनिसिपिल निकायों में सबसे बड़ी पार्टी बन कर उभरी, इन पांच निकायों में वह बहुमत में रही। कांग्रेस 15 निकायों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसमें से 11 में वह बहुमत में रही।

श्रीनगर नगर निगम (एसएमसी) में 74 सदस्यीय निकाय में 53 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते, जबकि कांग्रेस ने 16 और भाजपा ने चार वार्डों में विजय हासिल की।

जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा के अच्छे

प्रदर्शन करने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी पार्टी लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिये कड़ी मेहनत करेगी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, "मैं शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा का समर्थन देने के लिये जम्मू और कश्मीर के लोगों को धन्यवाद देता हूं।" प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के लोगों को आश्वस्त किया कि भाजपा राज्य के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये कड़ी मेहनत करेगी।

वहीं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने भी पार्टी के प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में शहरी निकाय चुनावों में प्रभावशाली प्रदर्शन से साफ है कि पार्टी ने राज्य के लोगों का विश्वास हासिल किया है। श्री शाह ने ट्वीट कर कहा, "ये नतीजे जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाते हैं, जिन्होंने झगड़े की राजनीति से आगे बढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास की राजनीति में भरोसा जताया। मैं भाजपा को समर्थन देने के लिये उनका शुक्रिया करता हूं और आश्वस्त करता हूं कि उनके सपनों को साकार करने के लिये हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे।'' ■

प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पुलिस स्मारक राष्ट्र को समर्पित

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21 अक्टूबर को पुलिस स्मारक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया। श्री मोदी ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने हॉट स्प्रिंग्स घटना के तीन जीवित सदस्यों को सम्मानित किया। श्री मोदी ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक के संग्रहालय का भी उद्घाटन किया और आगंतुक पुस्तिका में हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की सेवा करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले पुलिस कर्मियों के साहस और बलिदान को सलाम किया। उन्होंने हॉट स्प्रिंग्स लद्दाख में बहादुरी से लड़ने वाले बहादुर पुलिस कर्मियों के बलिदानों को याद किया और उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति सम्मान व्यक्त किया।

राष्ट्रीय पुलिस स्मारक राष्ट्र को समर्पित करने में खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस स्मारक की केंद्रीय मूर्तिकला पुलिस बलों की क्षमता, साहस और सेवा भावना का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय पुलिस स्मारक से जुड़ी हर वस्तु देश के नागरिकों को पुलिस और अर्धसैनिक कर्मियों की बहादुरी के बारे में शिक्षित करेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश जिस शांति, सुरक्षा और समृद्धि का आनंद उठा रहा है वह पुलिस, अर्धसैनिक और सशस्त्र बलों के लगातार प्रयासों के कारण ही संभव हुई है।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बलों और राज्य आपदा मोचन बलों के योगदान का भी जिक्र किया और कहा कि पुलिस और अर्धसैनिक बल राष्ट्रीय आपदा मोचन बलों का महत्वपूर्ण अंग है और आपदाओं से निपटने में उनके योगदान बहुत महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा इस स्मारक को एनडीए सरकार ने प्राथमिकता दी और इसे समय पर पूरा किया है। उन्होंने कहा कि यह स्मारक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों को अधिक से अधिक सम्मान देने के सरकार के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।

प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने पुलिस बलों से अपने दैनिक कर्तव्य के निर्वहन में प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने का अनुरोध किया। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना (एमपीएफ) का उल्लेख किया जो प्रौद्योगिकी, आधुनिक संचार प्रणालियों और आधुनिक हथियारों के माध्यम से पुलिस बलों का आधुनिकीकरण कर रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पुलिस बलों को पुलिस और समाज के बीच के बंधन को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने पुलिस बलों से पुलिस स्टेशनों को नागरिकों के अधिक अनुकूल बनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में केंद्रीय मूर्तिकला, कर्तव्य निभाते हुए अपने जीवन का बलिदान करने वाले पुलिसकर्मियों के नाम उत्कीर्ण हुई साहस और वीरता दर्शाने वाली दीवार तथा शहीद पुलिसकर्मियों की यादगार को समर्पित एक आधुनिक संग्रहालय शामिल है। ■

राष्ट्रीय पुलिस स्मारक

राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का निर्माण दिल्ली स्थित शांतिपथ के उत्तरी छोर पर चाणक्यपुरी में 6.12 एकड़ भूमि पर किया गया है। यह पुलिस स्मारक सभी राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश पुलिस बलों एवं केन्द्रीय पुलिस संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है। 1947 से अभी तक 34,844 पुलिस जवान शहीद हो चुके हैं, जिनमें 424 पुलिस जवानों ने इसी वर्ष अपनी शहादत दी है। इनमें से कई बहादुर जवानों ने कश्मीर, पंजाब, असम, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम जैसे विभिन्न क्षेत्रों एवं देश के वाम चरमपंथ क्षेत्रों में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपनी जानें गवाई हैं।

इसके अतिरिक्त, बड़ी संख्या में पुलिस के जवान अपराध रोकने एवं कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में शहीद हुए। एनपीएम ग्रेनाइट के एक टुकड़े से बनी केंद्रीय प्रस्तर प्रतिमा है जो 30 फीट ऊंचा पत्थर का खंभा है, जिसका वजन 238 टन है। इसका वजन और रंग सर्वोच्च बलिदान की गंभीरता का प्रतीक है। सभी 34,844 पुलिस जवानों के नाम शूरता की दीवार पर ग्रेनाइट पर उत्कीर्ण हैं। गौरतलब है कि 1959 में चीनी सैनिकों द्वारा लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स में मारे गये पुलिस जवानों की याद में प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मारक दिवस मनाया जाता है।

तेल उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच साझेदारी जरूरी: नरेन्द्र मोदी

कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के उछाल के बीच प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तेल उत्पादकों और उपभोक्ता देशों के बीच भागीदारी के संबंध पर जोर दिया, ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिल सके। ऊर्जा क्षेत्र के वैश्विक विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने 15 अक्टूबर को तेल एवं गैस बाजार में भारत की उल्लेखनीय हैसियत पर प्रकाश डाला। गौरतलब है कि तेल और गैस क्षेत्र के भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) ने प्रधानमंत्री श्री मोदी से भेंट की।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यह बात रेखांकित की कि तेल बाजार का संचालन उत्पादकों द्वारा किया जा रहा है और इसकी मात्रा एवं मूल्य दोनों का ही निर्धारण तेल उत्पादक देश करते हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो पर्याप्त उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन तेल क्षेत्र में विपणन के लिए अपनाए जाने वाले अनूठे तरीकों के कारण तेल के मूल्य बढ़ गए हैं।

श्री मोदी ने अन्य बाजारों की तर्ज पर तेल बाजार में भी उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच साझेदारी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे बेहतरी के मार्ग पर अग्रसर वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता आएगी।

श्री मोदी ने भारत के लिए प्रासंगिक माने जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों की ओर विशेषज्ञों का ध्यान आकृष्ट किया। पहला, प्रधानमंत्री ने इस बात पर रोशनी डाली कि कच्चे तेल के बढ़ते मूल्यों के कारण उपभोक्ता देशों को संसाधनों की भारी किल्लत सहित कई अन्य आर्थिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि इस खाई को पाटने के लिए तेल उत्पादक देशों के बीच सहयोग अत्यन्त जरूरी है। उन्होंने तेल उत्पादक देशों से अपनी निवेश योग्य अधिशेष (सरप्लस) राशि को विकासशील देशों के तेल क्षेत्र में वाणिज्यिक दोहन में लगाने का अनुरोध किया। दूसरा, उन्होंने उत्खनन अथवा खोज क्षेत्र का दायरा बढ़ाने का अनुरोध किया और इसके साथ ही विकसित देशों से प्रौद्योगिकी एवं विस्तार दोनों ही क्षेत्रों में सहयोग करने का आग्रह किया।

तीसरा, प्रधानमंत्री ने गैस वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर विशेष जोर दिया। प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी का उल्लेख करते हुए उन क्षेत्रों में सहायता देने का अनुरोध किया, जहां उच्च दबाव एवं उच्च तापमान से जुड़े तकनीकी अनुप्रयोगों (एप्लीकेशन) को प्राकृतिक गैस के वाणिज्यिक दोहन के लिए प्रासंगिक माना जाता है। आखिर में, प्रधानमंत्री ने भुगतान की शर्तों की समीक्षा करने का अनुरोध किया ताकि स्थानीय मुद्रा को अस्थायी राहत मिल सके।

प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में अपनी सरकार द्वारा की गई विभिन्न नीतिगत पहलों और विकास संबंधी विभिन्न उपायों का उल्लेख किया। उन्होंने गैस के मूल्य निर्धारण और विपणन में उदारीकरण पर प्रकाश डाला, क्योंकि विशेषकर इस मोर्चे पर भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इसके लिए उच्च दबाव तथा उच्च तापमान पर दोहन से जुड़ी प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पड़ती है।

उन्होंने खुली रकबा लाइसेंसिंग नीति, कोल बेड मिथेन का

जल्द मुद्रीकरण करने, छोटे क्षेत्रों की खोज के लिए प्रोत्साहन देने और राष्ट्रीय स्तर पर भूकंपीय सर्वेक्षण किए जाने का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने फिलहाल जारी वाणिज्यिक दोहन या उपयोग की चर्चा करते हुए विशेषकर उत्पादन साझेदारी अनुबंधों का विस्तार किये जाने का उल्लेख किया।

बातचीत के दौरान अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और सीईओ ने 'कारोबार में सुगमता' विशेषकर भारत के ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों में उठाए गए विभिन्न कदमों की सराहना की। विशेषज्ञों ने अपतटीय (अपस्ट्रीम) निवेश की दृष्टि से भारत की प्रतिस्पर्धी रैंकिंग में सुधार का उल्लेख किया जो 56वीं रैंकिंग से सुधरकर अब 44वीं रैंकिंग हो गई है।

इस दौरान अनेक विषयों पर चर्चा हुई जिनमें भारत में तेल व गैस क्षेत्र से जुड़े बुनियादी ढांचे का विस्तार करना, खोज एवं उत्पादन का दायरा बढ़ाना, सौर ऊर्जा एवं जैव ईंधनों में संभावनाएं ढूंढ़ना और ऊर्जा क्षेत्र के लिए केन्द्र सरकार की समग्र अवधारणा भी शामिल हैं। विशेषज्ञों ने इस तरह के संवाद की अनूठी पहल की सराहना की, क्योंकि इसकी बदौलत विभिन्न हितधारकों को नीतिगत विषयों पर एकजुट होने का मौका मिला।

इस अवसर पर उपस्थिति हस्तियों में सऊदी अरब एवं संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के मंत्रियों के साथ-साथ विभिन्न संगठनों जैसेकि सऊदी अरामको, एडनॉक, बीपी, रोजनेफ्ट, आईएचएस मार्किट, पॉयनियर नेचुरल रिसोर्सेज कम्पनी, एमरसन इलेक्ट्रिक कम्पनी, तेलुरियन, मुबादाला इन्वेस्टमेंट कंपनी, श्लमबर्गर लिमिटेड, वुड मैकेंजी, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए), एनआईपीएफपी और ब्रुकिंग्स इंडिया के सीईओ एवं विशेषज्ञ भी शामिल थे।

इसी तरह तेल एवं गैस की खोज, उत्पादन तथा विपणन में संलग्न भारतीय कंपनियों के सीईओ भी इस अवसर पर उपस्थित थे। केन्द्रीय मंत्री श्री अरुण जेटली एवं श्री धर्मेन्द्र प्रधान और नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार के अलावा केन्द्र सरकार एवं नीति आयोग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद थे। ■

दिल्ली में वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली की शुरुआत

केन्द्रीय पृथ्वी विज्ञान और पर्यावरण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 15 अक्टूबर को नई दिल्ली में दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली लांच की। यह प्रणाली गंभीर वायु प्रदूषण का पूर्वानुमान लगा सकती है और भारत सरकार के ग्रेडेड रेस्पोंस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के अनुसार आवश्यक कदम उठाने के लिए अलर्ट जारी कर सकती है।

वायु गुणवत्ता और प्रदूषण से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार द्वारा की गई पहलों के साथ ही समाज की भागीदारी भी जरूरी है। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए कृषि यन्त्रीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केन्द्रीय क्षेत्र की नई योजना के अंतर्गत 1151.80 करोड़ रुपये के व्यय में से केन्द्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लिए 591.65 करोड़ रुपये जारी कर चुका है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की 41 टीमों को मंत्रालय के 'आंख और कान' बताते हुए डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि दिल्ली और एनसीआर के शहरों गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में धूल और अन्य प्रकार के प्रदूषण के कम होने और उसे समाप्त करने के उपायों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के लिए

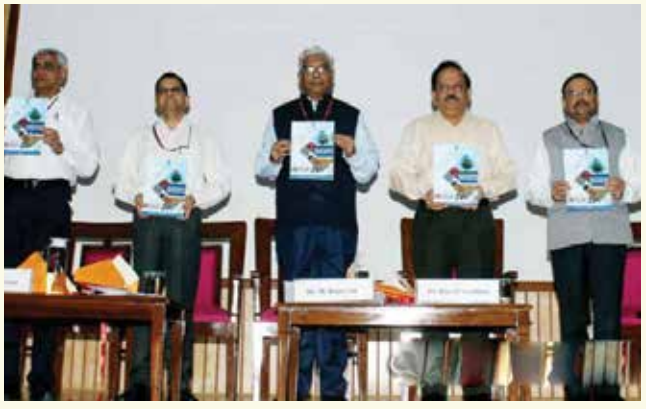

इन टीमों को निगरानी और निरीक्षण के लिए तैनात किया गया है।

साथ ही, वायु प्रदूषण रोकने के लिए तीन पायलट परियोजनाएं शुरू की गई हैं: दिल्ली के 7 ट्रैफिक चौराहों पर डब्ल्यूएवाईयू; मानव रचना यूनिवर्सिटी की 30 बसों पर वायु फिल्टर पर उच्च निर्माण स्थलों पर धूल बैठाने वाले रसायन; लैंड फिल स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और गार्ड तैनात किए गए हैं, ताकि इन स्थानों पर आग लगने की कोई घटना न हो। ■

सांस्कृतिक अधिष्ठान

भारतीय जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष एवं एकात्म मानववाद के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय द्वारा 4 जून, 1959 को कानपुर में संपन्न संघ शिक्षा वर्ग में दिए गए बौद्धिक का द्वितीय भाग:

दीनदयाल उपाध्याय

दुनिया की और चीज़ों में भी चैतन्य है, शक्ति है। इसका भी विचार करें। हमारी संस्कृति में हमने जो विचार किया तो केवल मानव का ही विचार नहीं किया, अपितु बाकी की सारी सृष्टि का भी विचार किया है। इस सृष्टि के साथ भी हमारी एकता है। उसके साथ हमारा संबंध है। इस सत्य का विचार करके कि हम सृष्टि से अलग पैदा नहीं हुए, किसी शून्य में पैदा नहीं हुए, यहां केवल मानव का ही विचार करेंगे, तो पशुभाव है। बहुत ही निम्न विचार है। साधारण पशु जीवन में भी तो हम यह देखते हैं। कि वह अपनी जाति के अन्य जीवों का विचार करता है। कौआ कौए का विचार करता है। यदि एक कौआ मर जाए तो बाक़ी के तमाम कौए इकट्ठे हो जाते हैं। चींटियों का बड़ा संगठन हम देखते हैं। किसी एक प्राणी शास्त्री ने कहा है कि यदि चींटियां बिल्ली के बराबर होतीं तो मनुष्य को उठा ले जातीं। उनके पास इतनी बुद्धि है कि जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ज्ञान की बातें पशुओं में भी दिखाई पड़ती हैं।

संपूर्ण सृष्टि के साथ हमने ही एकात्मता का विचार किया। इस एकात्मता का विचार एक भारतीय विचार है। इस आधार पर ही हमने सारे व्यवहारों को निश्चित किया और इसलिए जब हम अपनी संस्कृति का विचार करते हैं तो बताया कि सबके अंदर आत्मा है। अतः परार्थ भाव से ही विचार करते हैं। हम केवल अपना ही विचार करें, ऐसी बात नहीं है। आगे चलकर संपूर्ण सृष्टि का भाव लेकर हम विचार करते हैं, तो फिर प्रश्न होता है। कि सबके अंदर संपूर्ण सृष्टि का भाव लेकर परार्थ भाव के आधार पर हम सोचकर चलते हैं, यह व्यावहारिक कैसे होगा? परंतु हमने एक प्रकार से सबमें मेल बिठाया है और उसमें हमें अपने व्यावहारिक जीवन की राह छोड़नी पड़े, ऐसा नहीं होता है।

हमारा व्यावहारिक जीवन यह बड़े महत्त्व का है। यह हमारा शरीर चलना चाहिए। हमारी संस्कृति की विशेषता इसी में है कि हमने एक बहुत बड़ा उच्चतम आदर्श अपने सामने जीवन का रखा है। इसके अनुसार ही हमारा व्यवहार होता है। सत्य का हमने निरूपण किया है। परंतु उसके साथ-साथ दुनिया में जो एक व्यवहार रखा, उस व्यवहार के आधार पर सत्य का विचार करते हुए वास्तविकताओं की भी अपने संपूर्ण जीवन को चलाने में व्यवस्था की। अर्थात् यह एक ऐसी व्यवस्था है कि जीवन तो चले, परंतु इस प्रकार चले कि दूसरे के जीवन में भी व्यवधान न आने पाए।

साधारणतया देखा जाता है कि शरीर में ऐसी व्यवस्था है, जिसे व्यक्त करने के लिए आत्मा सत्य है, तो ठीक है। इसका विचार करके चलने की जरूरत है, जो आत्मा है, उसके आधार पर एकता हो सकती है, हमने तो इसके भी आगे विचार किया है। भगवान् का ही नहीं, सृष्टि का विचार भी हमने परार्थ भाव के आधार पर किया, क्योंकि इससे ही व्यावहारिक जीवन चल सकता है। इन विशेषताओं को ही जीवन का उत्तम आदर्श बनाया। अपने समान की सृष्टि के प्रत्येक जीव में आत्मा है, यह विचार हमने सदैव किया। आत्मा के चैतन्य का ही नहीं, उसके लिए शरीर की आवश्यकता का भी हमने ध्यान रखा, जैसे हमने यह सोचा कि रोटी खाने से क्या लाभ, क्योंकि प्रतिदिन सुबह-शाम खाते-पीते भी शरीर का अंत होना है। अतः ज्ञान की बात ही अच्छी होती है। परंतु कोरे ज्ञानमात्र से ही कार्य का होना संभव नहीं। अतः जीने के लिए भोजन करना ही होगा। सबमें एक आत्मा का भाव रखते हुए भी यथायोग्य व्यवहार का ध्यान रखते हैं। जैसे-एक कुत्ता, ब्राह्मण तथा हाथी हैं और ये सभी भूखे हैं। यदि ब्राह्मण की खीर हाथी को खिला दी और हाथी का खाना कुत्ते को खिला दिया, तो यह तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका हम सहज ही विचार कर सकते हैं। अतः वास्तविकताओं का विचार ही जीवन का विचार करना होता है।

राष्ट्र की एक सत्ता है। इससे अलग व्यक्ति की भी अपनी एक हस्ती है। इतना ही नहीं, तो व्यक्ति और राष्ट्र के बीच कुटुंब व

संपूर्ण सृष्टि के साथ हमने ही एकात्मता का विचार किया। इस एकात्मता का विचार एक भारतीय विचार है। इस आधार पर ही हमने सारे व्यवहारों को निश्चित किया और इसलिए जब हम अपनी संस्कृति का विचार करते हैं तो बताया कि सबके अंदर आत्मा है। अतः परार्थ भाव से ही विचार करते हैं। हम केवल अपना ही विचार करें, ऐसी बात नहीं है।

अन्य इकाइयों का अपना विशेष महत्त्व है। उन्हें भुलाकर कोई कार्य करना संभव नहीं। जैसे यदि हमने यह विचार रखा कि संपूर्ण संपत्ति राष्ट्र की है। अतः बच्चा भी राष्ट्र का है। फिर उसके पालन-पोषण की जिम्मेवारी राष्ट्र की हो जाती है। परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बच्चे के जीवन के विकास में मां का विशेष हाथ रहता है। उससे बच्चे को अलग कर उसका सही विकास संभव नहीं। अतः व्यक्ति को परिवार और परिवार को राष्ट्र से संबंध जोड़ना और उन्हें एक-दूसरे का पूरक बनाने का प्रयास चलता रहता है। यह एक प्रकार की व्यवस्था है, इसमें व्यक्ति, कुटुंब, ग्राम, जनपद, राष्ट्र एवं विश्व तथा संपूर्ण सृष्टि तक आती है। इनका आपस का संबंध स्थापित करते हुए एक-दूसरे का पूरक बनाया जाना चाहिए।

यह बात अवश्य है कि किसी विशेष संकट के समय किसी को कितना महत्त्व दिया जाए, इस पर विचार करना पड़ेगा। अपने यहां तो अत्यंत प्राचीन काल से विचार होता चला आया है, जैसे-

त्यजेत एकं कुलस्यार्थे, ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत।
ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत।।

कुल के लिए यदि व्यक्ति बाधक है तो उस व्यक्ति को त्याज्य मानो। इसी प्रकार गांव के लिए कुल को, जनपद के जिए गांव को और आत्मा के लिए पृथ्वी का त्याग उचित बताया गया है। जब श्रीकृष्ण ने देखा कि यादव आपसी द्वेषभाव से पीड़ित हैं, तब उन्होंने कौरवों-पांडवों का युद्ध करा दिया। यह युद्ध यानी महाभारत का युद्ध राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर ही हुआ। इस कार्य में बंधु एवं संबंधी भाव मार्ग में बाधक नहीं हुए। इस प्रकार के अनेक उदाहरण अपने को भारत के इतिहास में मिलेंगे। इस विचार के कारण ही जब-जब राष्ट्र के ऊपर आपत्ति हुई, केवल एक राष्ट्रभाव को सम्मुख रखकर हमने कार्य किया और तभी देश की रक्षा संभव हो पाई।

पाश्चात्यों के अनुसार राष्ट्र मनुष्यकृत है, ऐसा हमने कभी नहीं माना। इसके विपरीत हम तो राष्ट्र को ईश्वरकृत मानते हैं। यदि राष्ट्र बनता भी है तो भी इसके पीछे हजारों वर्षों का इतिहास रहता है। हमने राष्ट्र को इकरारनामा कभी नहीं माना। अतः पाश्चात्य भावों से प्रेरित होकर इस राष्ट्र की एकता के प्रयत्न असफल हुए। संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करने का स्वप्न साकार करने का प्रयास करनेवाले सिकंदर को भी यदि कहीं हार खानी पड़ी तो अपने ही देश में। इसके पीछे अन्य कोई भाव नहीं था। राष्ट्रीयता का भाव ही मुख्य था। यूरोप में सभी ईसाई हैं। रोम का पोप सब कुछ था। इस आधार पर उन लोगों ने संपूर्ण यूरोप को एक करने का प्रयास किया। परंतु इसमें हमने देखा कि प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स में ही महान् संघर्ष हुए।

हम तो राष्ट्र को ईश्वरकृत मानते हैं। यदि राष्ट्र बनता भी है तो भी इसके पीछे हजारों वर्षों का इतिहास रहता है। हमने राष्ट्र को इकरारनामा कभी नहीं माना। अतः पाश्चात्य भावों से प्रेरित होकर इस राष्ट्र की एकता के प्रयत्न असफल हुए। संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करने का स्वप्न साकार करने का प्रयास करनेवाले सिकंदर को भी यदि कहीं हार खानी पड़ी तो अपने ही देश में।

इसके पीछे भी राष्ट्रीयता मूल कारण थी। जहां कहीं ये सफल भी हुए उन स्थानों पर राष्ट्रीयता के पुनर्जागरण ने उन्हें जड़ से समाप्त कर दिया। इसलाम में भी इसी प्रकार, का एक प्रयास हमें दिखाई पड़ता है। सारी दुनिया को इसलाम धर्म के झंडे के नीचे लाकर उन्हें एकसूत्र में बांधने का प्रयत्न भी मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानकर चलने वालों के द्वारा हमने देखा। स्पेन से लेकर ईरान तक इनके सामने लोग झुक गए, किंतु अगर इनको भी कहीं हार खानी पड़ी तो भारत में ही। यद्यपि इनका साम्राज्य बहुत दिनों तक हमारे देश में था, परंतु राष्ट्रीयता के जाग्रत् भाव के कारण ही इनको यहां असफलता मिली। प्रसिद्ध मुसलिम कवि हाली ने भी कहा है कि जो इसलाम दुनिया के सुदूर देशों में कितने ही समुद्रों को, दुर्लंघ्य पर्वतों को पार करता चला गया, वह गंगा के दहाने में आकर डूबा।

इसी प्रकार प्रारंभ में तो संपूर्ण ईरान इनके प्रभाव में आ गया, परंतु जब वहां राष्ट्रीयता ने जोर पकड़ा तो इनके आडंबर को उखाड़ बाहर फेंका। ईरानी नेता रजा पहलवी ने अपने को श्रेष्ठ आर्य कहकर इनको वहां से समाप्त कर दिया। प्रथम महायुद्ध के बाद अंग्रेजों ने मुसलमान जगत् के ख़लीफ़ा को जब पदच्युत कर दिया तो उनको पुनः प्रतिष्ठित कराने का प्रयास इसलाम के अनुयायियों ने किया। हमारे देश में भी असहयोग आंदोलन के समय यह प्रश्न उठा और मुसलिम एकता के स्वप्न को साकार करने के लिए हमने भी इस आंदोलन के सहयोग में हाथ बढ़ाया, परंतु कुछ ही दिनों बाद देखा गया कि जब तुर्की में राष्ट्रीयता ने जोर पकड़ा तो इसलाम के इस स्वरूप को देश से बाहर फेंक दिया। आज वहां के लोग तुर्क के नाते अपना विचार करते हैं, न कि इसलाम के अंग के रूप में।

पाकिस्तान का उदाहरण तो हमारे सामने ही है। यद्यपि उन्होंने इसलाम के नाम पर इस राज्य का निर्माण किया, परंतु अपनी कल्पित राष्ट्रीयता का आधार लेकर उन्हें अपनी समस्याएं हल करनी पड़ रही हैं। यदि केवल धर्म का विचार होता तो अफगानिस्तान से उनकी टक्कर का कोई प्रसंग ही न उठता। मिस्र, इराक, अरब तथा अन्य मध्यपूर्व के राज्य यद्यपि इसलाम में विश्वास करते हैं, परंतु उन सबकी स्वतः एक-एक स्वतंत्र इकाई है। इतना ही नहीं, उनमें आपस की टक्कर भी प्रतिदिन की घटना है। इसके पीछे भी राष्ट्रीयता का ही प्रधान भाव है। ■ *क्रमशः...*

नहीं रहे भाजपा सांसद भोला सिंह

(3 जनवरी 1939 – 19 अक्टूबर 2018)

बेगूसराय के भाजपा सांसद श्री भोला सिंह नहीं रहे। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 19 अक्टूबर को उन्होंने अंतिम सांस ली। 79 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। श्री भोला सिंह राजनीति में अपनी शुचिता और सरल हृदय के लिए जाने जाते थे। सामाजिक कार्यों में उनकी गहरी अभिरुचि थी और वे लोगों में काफी लोकप्रिय थे। श्री सिंह बिहार के वरिष्ठतम राजनेताओं में से एक थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित अनेक बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि दी।

जीवन–परिचय

श्री भोला सिंह का जन्म 3 जनवरी 1939 को हुआ था। छात्र जीवन से ही राजनीति में उनकी दिलचस्पी थी। वर्ष 1967 में पहली बार निर्दलीय विधायक बने। इसके बाद 1972 में सीपीआई, 1977, 1980 और 1985 में कांग्रेस से विधायक बने। फिर वर्ष मार्च 2000 और नवंबर 2005 में वे भाजपा के टिकट पर बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए।

वर्ष 2003 से 2005 तक विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। बिहार सरकार में वे गृह राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्री और नगर विकास मंत्री रहे। 2009 में नवादा से पहली बार सांसद बने। 2014 में वे बेगूसराय से लोकसभा सदस्य चुने गए।

अपने लोकहित कार्यों के नाते श्री भोला सिंह बेगूसराय के जननेता थे। आम जन के प्रति उनका प्रेम ही था, जिससे वे विरोधियों के बीच भी स्वीकार्य थे। सच तो यह कि श्री सिंह बेगूसराय के अजातशत्रु थे। ■

शोक सन्देश

बेगूसराय से सांसद भोला सिंह जी के निधन से दुःखी हूं। उनके उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों तथा बिहार के विकास हेतु उनके प्रयासों के लिए उन्हें याद किया जाएगा। दुःख की इस घड़ी में उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है।

– नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

श्री भोला सिंह की मृत्यु बिहार के लिए बड़ी क्षति है। श्री सिंह सामाजिक कार्य में सक्रियता से भाग लेते थे और उनके जाने से इस क्षेत्र को भी बड़ा नुकसान हुआ है। उनके जैसे सहज सक्रिय समाज सेवा के लिए समर्पित व्यक्तित्व का जाना उनके क्षेत्र व समूचे बिहार के लिए गहरी क्षति है।

– सुमित्रा महाजन, लोकसभा अध्यक्ष

भाजपा सांसद भोला सिंह जी के निधन की दुःखद सूचना प्राप्त हुई। भोला सिंह जी का जीवन बिहार की जनता के विकास व उनकी समस्याओं के निवारण के लिए समर्पित रहा। वह बेगूसराय विधानसभा से आठ बार चुने गये। मैं दुःख की इस घड़ी में उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।

– अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

साईं से मिलती है जनसेवा की प्रेरणा: नरेन्द्र मोदी

शिरडी के साईं बाबा को समाधि लिए हुए 19 अक्टूबर को 100 साल पूरे हुए। इस विशेष अवसर पर शिरडी में संपन्न एक भव्य समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित रहे। शिरडी पहुंचकर श्री मोदी ने पूजा-अर्चना की और विशेष आरती में भी शामिल हुए। इसके बाद यहां नए भवन, 159 करोड़ रुपये की लागत से विशाल शैक्षणिक भवन, प्लेनेटोरियम, वैक्स म्यूजियम, साईं उद्यान और थीम पार्क समेत अन्य प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण करने के साथ ही भूमिपूजन भी किया।

प्रधानमंत्री ने ओम साईंनाथ से अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने देशवासियों को विजयादशमी की बधाई देते हुए कहा, 'जैसे सब अपनों के साथ त्योहार मनाना चाहते हैं, वैसे ही मेरा प्रयास रहता है कि हर त्यौहार देशवासियों के बीच जाकर मनाऊं। आपका अपनत्व ही मेरी सामर्थ्य है और आपका प्यार मुझे शक्ति देता है।'

उन्होंने कहा, 'थोड़ी देर पहले मैंने साईं बाबा के दर्शन किए और आशीर्वाद मिला। मैं जब भी उनके दर्शन करता हूं, जनसेवा की भावना और इसके लिए खुद को समर्पित करने का उत्साह मिलता है।' उन्होंने कहा, 'शिरडी तात्या पाटील, माधवराव देशपांडे और तुकाराम जैसे महापुरुषों की धरती है और मैं इन्हें नमन करता हूं।'

साईं महिमा पर श्री मोदी ने कहा, 'सबका मालिक एक है, साईं के ये चार शब्द समाज को एक करने का सूत्र वाक्य बन गए हैं। साईं समाज के थे और समाज साईं का था।' उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए कई योजनाओं का आज पावन जगह से शिलान्यास किया, इसके लिए राज्य सरकार बधाई की पात्र है।

प्रधानमंत्री ने यहां शुभारंभ हुईं योजनाओं को लेकर कहा कि इस दशहरा साईं बाबा ट्रस्ट की ओर से मिले ये अनेक तोहफे हैं। उन्होंने कहा, 'मैं खुश हूं कि मुझे राज्य के करीब ढाई लाख भाई-बहनों को उनका घर सौंपने का अवसर मिला है। एक साथ गृहप्रवेश कराने जैसी गरीब भाई-बहनों की सेवा से बढ़कर दशहरे की पूजा और क्या हो सकती है।'

आवास योजना को लेकर श्री मोदी ने कहा, 'बीते चार साल में गरीब को झुग्गी से निकालकर घर देने का काम किया गया है। पहले भी कोशिशें हुईं, लेकिन उन कोशिशों का लक्ष्य घर देने के बजाय एक विशेष परिवार का प्रचार करना था।' कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब किसी योजना में राजनीतिक स्वार्थ के बजाय सिर्फ गरीब का कल्याण होता है, तो काम की गति कैसे बढ़ती है यह सामने है।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'पिछली सरकार ने चार साल में 25 लाख घर बनाए थे और हमने अपने चार साल में एक करोड़ 25 लाख घर बनाए हैं। इतने के लिए उन्हें 20 साल लग जाते और आपको इंतजार करना पड़ता।' उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 2022 तक घर व्यक्ति को उसका पक्का घर देने का है और अगर नीयत साफ हो, भावना अच्छी हो, तो उन्हीं संसाधनों और उन्हीं लोगों के साथ काम तेज गति से होता है।

कांग्रेस को घेरते हुए श्री मोदी ने कहा कि पहले एक परिवार के प्रचार के लिए घर बनते थे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने चार साल में गरीब को झुग्गी से निकालकर घर देने का काम किया है, जबकि पहले इस तरह के प्रयास का उद्देश्य एक विशेष परिवार के नाम का प्रचार करना अधिक होता था। इस दौरान श्री मोदी ने राजग सरकार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया।

संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि देश के हर गरीब को घर देना हमारी सरकार का लक्ष्य है। जनसेवा में शिरडी का उदाहरण सबसे आगे है। गरीबों के कल्याण के लिए शिरडी से बेहतर जगह और कोई नहीं। ■

यूपीए सरकार में बांटे गए अंधाधुंध कर्ज से हुई बैंकिंग व्यवस्था की हालत खराब

अरुण जेटली

मीडिया में कुछ बीमार, भ्रमित और गलत लेखों के कारण बैंकों की छवि कर्ज माफ करने वाली संस्था के तौर पर बनाते हुए कई ट्वीट्स और सोशल मीडिया पोस्ट आज हमारी नजर में आ रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ राजनेता अपने गैर जिम्मेदाराना बयानों से इस समस्या को और भी जटिल दिखाने का प्रयास कर रहे है, जिन्होंने कर्ज़ माफी की तुलना कोरपोरेट सेक्टर को खैरात बांटने के तौर पर की है, जबकि यह एक सामान्य प्रक्रिया है।

इसलिए हमारी जटिल बैंकिंग प्रक्रिया और लेखांकन के मुद्दे पर सरल और सही परिप्रेक्ष्य रखना बेहद जरुरी हो गया है।

पिछले 10 वर्षों में हमारी बैंकिंग प्रणाली ने नियामक और कानूनी ढांचे में दो अलग-अलग व्यवस्थाओं को देखा है। जिसमें पहली व्यवस्था को 'उत्तरदायित्व के बिना ऋण मुहैया कराना' कहा जा सकता है, जो यूपीए-1 सरकार के कार्यकाल के अंतिम दिनों से शुरू हुई और यूपीए-2 सरकार में जारी रही।

इस दौरान बैंकिंग प्रणाली, विशेष तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के बकाया ऋण में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई, जो मार्च 2008 के 18 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2014 में 52 लाख करोड़ रुपये हो गई। इस अवधि की एक विशेषता यह रही कि इस दौरान कर्जदारों की क्रेडिट मूल्यांकन जांच में घोर लापरवाही बरती गई और उन्हें कर्ज देने के लिए एक आक्रामक रवैया अपनाया गया।

हालांकि कर्ज देने में आक्रामक रवैया अपनाने के चलते आर्थिक विकास में वृद्धि भी देखी जा सकती है, लेकिन इस प्रणाली को अपनाने के लिए पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए। वहीं, कर्जदार के उचित मूल्यांकन के अभाव में बकाया ऋण की समस्या के कारण बैंकों के फंसे कर्जों (एनपीए) में असाधारण वृद्धि देखी जाती है। यूपीए सरकार में संपत्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) की उपेक्षा और ऋण के लगातार पुनर्गठन से एनपीए की समस्या और भी खराब हो गई थी।

कर्ज की शर्तो में होने वाले लगातार बदलावों ने बैंकिंग प्रणाली में विकास की एक झलक दिखाने का प्रयास किया, लेकिन इस व्यवस्था के चलते एनपीए में केवल वृद्धि ही दर्ज ही की गई। इस पूरी व्यवस्था ने कर्ज प्रणाली में इरादतन धोखाधड़ी और खराब मूल्यांकन की पद्धति को जन्म दिया, जिसके चलते लापरवाही से कर्ज देने की प्रवृति को बल मिला और इसी प्रणाली ने देनदारों की क्षमता को भी प्रभावित किया।

वहीं, साल 2014 में एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद बैंकों पर लगातार बढ़ते एनपीए के दबाव को कम करने के लिए हमने जरुरी कदम उठाए, जिसके कारण इस व्यवस्था में एक आदर्श बदलाव आया। भारत सरकार ने साल 2015 में भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा अमल में लाई गई एक्यूआर प्रक्रिया को सख्ती से लागू कर तनावग्रस्त परिसंपत्तियों और एनपीए की पहचान करने का काम शुरू किया। इस पूरी प्रक्रिया के कारण कर्ज देने में लचीलेपन और लापरवाही की समस्या को सामने लाया जा सका, इस दौरान पाया गया कि कर्ज के पुनःवर्गीकरण और पुनर्गठन के मामलों में सावधानी नहीं बरती गई और यही बैंकों के एनपीए में असाधारण बढ़ोत्तरी का कारण बना।

साल 2014 में एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद बैंकों पर लगातार बढ़तें एनपीए के दबाव को कम करने के लिए हमने जरुरी कदम उठाए, जिसके कारण इस व्यवस्था में एक आदर्श बदलाव आया। भारत सरकार ने साल 2015 में भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा अमल में लाई गई एक्यूआर प्रक्रिया को सख्ती से लागू कर तनावग्रस्त परिसंपत्तियों और एनपीए की पहचान करने का काम शुरु किया।

इस संदर्भ में कर्ज के पुनः वर्गीकरण और पारदर्शी एक्यूआर के प्रभाव को इस बात से समझा जा सकता है कि मार्च 2014 में जहां सार्वजनिक बैंको के एनपीए 2.26 लाख करोड़ रुपये थे, वह मार्च 2018 में बढ़कर 8.96 लाख हो गए। किसी भी प्रभावी दिवालियपन तंत्र के अभाव में इन इरादतन घपलेबाजों ने अपने कर्ज की शर्तो को आसानी से बदलने और उनको एनपीए में शामिल होने से रोकने के लिए सभी संभावित हथकंडों को अपनाने का काम किया।

इस संदर्भ में भारत सरकार ने दूसरा महत्वपूर्ण कदम यह उठाया कि साल 2016 में कॉर्पोरेट, साझेदारी फर्मों और व्यक्तिगत दिवालियापन का प्रस्ताव देने के

लिए दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) का एलान किया, जिसमें इस पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध किया गया और साथ ही इसमें संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करने का प्रस्ताव भी दिया गया। वहीं, इसके नियामक ढांचे के संस्थागतकरण करने की बात भी इसमें कहीं गई।

इसके माध्यम से कॉर्पोरेट दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया (सीआईआरपी), फास्ट ट्रैक रिज़ॉल्यूशन, कॉर्पोरेट विघटन, स्वैच्छिक विघटन, इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स (आईपीएस), इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसियां (आईपीए), इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल एन्टीटीएज (आईपीई), इंफार्मेशन यूटिलिटीज और वैल्यूएटर के एकीकृति करने का प्रयास किया गया।

इससे विघटन और विवाद समाधान के लिए एक तंत्र तैयार हुआ, जिसमें निर्णय लेने वाले प्राधिकारी, दिवालियापन बोर्ड ऑफ इंडिया (आईबीबीआई), लगभग 2,000 आईपीएस, 81 आईपीई, 31 पीए, एक आईयू और पांच पंजीकृत वैल्यूर्स शामिल थे। वहीं जून 2016 और जुलाई 2018 के दौरान एनपीए का सामना कर रहे लगभग 1,100 कार्पोरट सीआईआरपी के लिए सामने आए, और लगभग 250 कार्पोरट ने स्वैच्छिक विघटन का प्रस्ताव दिया।

इस दौरान जुलाई 2018 तक 45 कॉर्पोरेट देनदारों ने सीईआरपी के लिए संकल्प प्रस्तुत किया है। आरबीआई ने 12 बड़े खातों में से चार मामलों में संकल्प प्रस्तुत किया और एक पर्याप्त राशि को जारी भी किया।

आईबीसी के सख्ती के चलते बहुत कम समय में ही बकायदारों के व्यवहार में एक परिवर्तन देखा गया है। यही कारण है कि देनदारों के अंदर अब अपना कर्ज तय समय-सीमा के अंदर या उससे पहले चुकाने की प्रवृति उत्पन हो रही है। आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान बैंक भी आईबीसी से इतर अपना कर्ज वसूलने में कामयाब होते दिखाई दे रहे है। आईबीसी के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के समक्ष दायर आवेदनों में 12 ऋण खातों ऐसे भी रहे, जिन्होंने अपने आवेदन स्वीकार होने से पहले वापस ले लिए और इससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों को सितंबर 2018 तक 449.76 करोड़ रुपये की राशि वसूल में कामयाबी हासिल हुई।

इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, भारत सरकार ने देनदार और लेनदारों दोनों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। एक तरफ जहां अनुपालन और वसूली के पहलुओं पर जोर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ, लेनदारों के व्यावहारिक परिवर्तन पर भी जोर दिया गया। इस कानूनी और नियामक ढांचे के परिणामस्वरूप प्रमोटर और देनदार अब अपनी पहचान डिफॉल्टर्स के रूप में नहीं चाहते।

किसी भी कार्यवाही से बचने के लिए, ऐसे देनदारों ने सीआईआरपी की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही अपने आवेदन वापस ले लिए हैं और बकाया राशि का भुगतान भी कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों और बैंक बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार ऐसे गैर-निष्पादित ऋण जिनमें चार साल के पूरा होने पर पूर्ण प्रावधान किया गया है, उनको बैंक के बैलेंस शीट से हटा दिया गया हैं।

एनपीए को बैंकों द्वारा अपनी बैलेंस शीट से हटाना और कर कार्यनिष्पत्ति बैंकों की एक सामान्य प्रक्रिया है। ऋण को राइट ऑफ करना लेखांकन की प्रक्रिया है जिससे कर और पूंजी अनुकूलन में मदद मिलती है। ऐसे राइट ऑफ ऋणों के बकायादार उसके पुनर्भुगतान के लिए उत्तरदायी बने रहतें है और कानून के तहत इनसे बकाया राशि की वसूली होती है, जिसमें वित्तीय संपत्तियों के सुरक्षा और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज के प्रवर्तन (सरफासी) अधिनियम और ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटीएस) के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

भारत सरकार ने ऋणों को पुनः वर्गीकृत और पुनर्मूल्यांकन करके, साथ ही आईबीसी के हस्तक्षेप के माध्यम से इरादतन घपलेबाजी करने वाले और नकली देनदारों के खिलाफ अपने संकल्प को दिखाया है। अपनी इस कार्यवाही के माध्यम से सरकार बैंकों के बीच अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को जन्म देना चाहती है। ■

(लेखक केंद्रीय वित्त मंत्री हैं)

भारत का नव-तीर्थ - स्टैच्यू ऑफ यूनिटी

— ओमप्रकाश धनखड़

राष्ट्र जीवन के संदर्भों में व्यक्ति का जीवन काल बहुत छोटा होता है, परंतु कुछ राष्ट्र निर्माताओं की छाप सदियों तक क़ायम रहती हैं। अमेरिकी राष्ट्र जीवन में जैसे अब्राहम लिंकन व द. अफ्रीका के राष्ट्र जीवन में नेलसन मंडेला का स्थान बना है, वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की अमिट छाप सदियों तक भारत के राष्ट्र जीवन में रहने वाली है।

राजनैतिक जीवन में श्रेय की हेराफेरी स्वाभाविक लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्तासीन शासक समस्त श्रेय स्वयं लेने के प्रयासों में महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों की जन स्मृति में पहुंच एंव उसके क़ायम होने से रोकने का सतत प्रयास करते है। ऐसे ही कारणों से भारत में भी अनेक महान व्यक्तित्व उनके योगदान के अनुरूप स्थापित नहीं होने दिए गए। सरदार उन्हीं शख्सियतों में से एक हैं, जिनका योगदान बहुत बड़ा है किंतु उनकी प्रतिमा लघु रखने का प्रयास रहा।

अब विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा उनके योगदान के अनुरूप साधू बेट, सरदार सरोवर बांध पर नर्मदा जिले में, वडोदरा से 90 किलोमीटर दूर स्थापित होने वाली है। शिलान्यास के समय तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री व अनावरण के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन व निर्णय से ये प्रतिमा प्रकाश-स्तम्भवत सदियों तक यह खड़ी रहेगी।

सरदार के योगदान को समझने के लिये कुछ सवाल खड़े करने ज़रूरी है। यदि सरदार नहीं होते तब क्या तत्कालीन भारत एकजुट होता? भारत के अनेक स्वतंत्र टुकड़े ब्रिटिशर्स जैसे छोड़कर जाना चाहते थे वे स्वतंत्र देश बनते? बिना भौगोलिक सम्पर्क के भी पाकिस्तान हमारे बीच-बीच में होता? विभाजित भारत के ये टुकड़े शत्रुभाव के साथ जैसे आज हमसे पाकिस्तान लड़ रहा हैं, कितने लड़ते? अपने ही तीर्थों के दर्शन के लिये जैसे आज हम चीन, पाकिस्तान व बांगलादेश का वीज़ा लेकर जाते है, क्या सरदार के अपने गुजरात के जूनागढ़ में, तेलंगाना के हैदराबाद में, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में हमें वीज़ा लेकर जाना पड़ता? सरदार के काम का आकलन 1947- 1950 के वर्षों व उन स्थानों से गुज़रे बिना नहीं हो सकता जहां से वो गुज़रे थे।

भारत के अनेक विद्वान भारत को सांस्कृतिक राष्ट्र कहते है। भारत एक प्राचीन राष्ट्र है, जिसकी राष्ट्रीयता का आधार, एक राज्य इकाई नहीं, एक संस्कृति है। क्या 565 अलग अलग राज्य इकाइयों के साथ, वर्तमान भारत विश्व में अपना स्थान बना पाता? राष्ट्र राज्य सिद्धांत को मानने वाले लोग, एक भूमि के टुकड़े पर, एक शासन की ईकाई स्थापित होने पर ही राष्ट्र के स्वरूप को स्वीकार करते है। यही वर्तमान विश्व की हक़ीक़त भी है।

इस सांस्कृतिक-राष्ट्र को, राष्ट्र-राज्य बनाने का श्रेय, केवल और केवल सरदार के नाम है। यह राष्ट्र, राष्ट्र-राज्य के वर्तमान स्वरूप के बिना अपनी नियति को पाने में विफल रहता। सांस्कृतिक राष्ट्रों का भी अंतिम ध्येय एक सशक्त राष्ट्र के रूप में खड़ा होने का होता है, जिसका शासन तंत्र भी एक हो।

स्टैच्यू आफ यूनिटी, वर्तमान भारत के भारत बनने की कथा भी है, तथा उस शिल्पी को श्रद्धांजलि भी है, जिसने स्वतंत्रता के समय भारत को एकजुट कर राष्ट्र के रूप में खड़ा किया था। यह इतिहास के पन्नों को नई पीढ़ी के सामने खोलने की पाठशाला भी हैं। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा खड़ी होकर खुद एक इतिहास की भी रचना करने जा रही हैं। सरदार भारत की एकता व अखंडता का जो कार्य जीवन

में करके गये, वही नव भारत के राष्ट्रीय-तीर्थ के रूप में खड़ी होने वाली, ये लौह पुरूष की प्रतिमा करेगी। भारत के हर एक गांव से आये किसान के प्रयुक्त लोहे व हर गांव के देवस्थान से आई, भावनाओं से भरी पवित्र मिट्टी से जो बनी है। यदि हम सरदार के व्यक्तित्व व कृतित्व में उतरेंगे तो सरदार की ऊंचाई से भी जुड़ सकेंगे जो अपनी प्रतिमा के समान ऊंची है। भारत का यह नवतीर्थ, इस राष्ट्र के शौर्य का वर्तमान पीढ़ी से परिचय करायेगा तथा इज़राइल के यादेवशम् म्यूज़ियम की तरह छुपाये गये इतिहास के पन्नों को खोलेगा। सरदार की 144 वीं जयंती के मौके पर अब उनकी प्रतिमा लघु नहीं रहेगी, उनके व्यक्तित्व के अनुरूप विराटरूप में खड़ी होगी। ■

(लेखक स्टैच्यू आफ यूनिटी के लिये लौह मिट्टी संग्रहण के राष्ट्रीय कोर्डिनेटर व वर्तमान में हरियाणा के कृषि व पंचायत मंत्री है।)

मानवाधिकार की रक्षा हमारी संस्कृति का बेहद अहम हिस्सा रहा है: नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की स्थापना दिवस के रजत जयंती कार्यक्रम पर 12 अक्टूबर को लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले ढ़ाई दशक में मानवाधिकार आयोग ने पीड़ित और वंचित लोगों की आवाज बनकर देश के निर्माण में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार की रक्षा हमारी संस्कृति का बेहद अहम हिस्सा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि देश की आजादी के बाद स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, सक्रिय मीडिया, सक्रिय समाज और एनएचआरसी जैसी संस्थाएं मानव अधिकार की रक्षा के लिए आगे आई।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवाधिकार सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि ये हमारे स्वभाव का हिस्सा होना चाहिए। पिछले लगभग 4 सालों में गरीबों का जीवन स्तर बेहतर करने के लिए कई गंभीर प्रयास किए गए। उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान सभी भारतीयों की मूलभूत जरुरतों को पूरा करने का रहा है। 9 करोड़ से ज्यादा शौचालयों के निर्माण से करोड़ों गरीब परिवारों को स्वच्छ और गरिमापूर्ण जिंदगी सुनिश्चित हुई है।

उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत हाल में शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने केंद्र सरकार की वित्तीय समावेशी योजना के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से राहत दिलाने के लिए बनाया गया कानून भी लोगों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए उठाए गए कदम में से एक है।

श्री मोदी ने न्याय प्रणाली को आसान बनाने के लिए ई-न्यायालय की संख्या बढ़ाना, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड को मजबूत करने जैसे उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने आधार को भी सशक्तिकरण के लिए एक तकनीकी आधारित उपक्रम बताया।

मानवाधिकार भारत की संस्कृति और स्वभाव में अंतर्निहित है: राजनाथ सिंह

केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने संबोधन में कहा कि 25 साल पहले स्थापित किए गए एनएचआरसी ने इस दौरान कई बार मील के पत्थर को छुआ है और देश की संस्थाओं के बीच अपनी खास जगह बनाई है।

उन्होंने कहा कि मानवाधिकार भारत की परंपरागत संस्कृति और स्वभाव में अंतर्निहित है। हमारे देश में हम सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि सबके साथ अच्छा हो और किसी के साथ बुरा न हो। भारत दुनिया में पहला देश है जो कि सिर्फ मनुष्यों का ही नहीं जानवरों के अधिकारों की रक्षा का ध्यान रखा। मानवाधिकार के लिए किसी राजपत्र की जरूरत नहीं महसूस हुई, क्योंकि ये भारत के मूल स्वभाव में ही निहित है।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मेरा विश्वास है कि कड़ी कार्रवाई के नाम पर अमानवीय कार्रवाई के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन मेरा इस बात पर भी पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय और सामाजिक हितों में लिए गए फैसलों को मानवाधिकार उल्लंघन के नजरिए से नहीं देखना चाहिए।

उन्होंने ये भी कहा कि कई बार कुछ लोग अपराधियों/आतंकियों के मानवाधिकार को लेकर चिंता जाहिर करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे अपराधी/आतंकवादी जब न सिर्फ दूसरों के मानवाधिकार का उल्लंघन करते हैं, बल्कि उनके जीने का अधिकार छीन लेते हैं तो ऐसी स्थिति में उन अपराधियों/आतंकवादियों के मानवाधिकार का मुद्दा हम कैसे उठा सकते हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि मानवाधिकार को उचित संदर्भ में देखा जाना चाहिए। मानवाधिकार का मतलब है कि सभी को सम्मानित जीवन जीने का अधिकार है। हमारी सरकार ने इस दिशा में करोड़ों लोगों के फायदे के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की जिसके तहत भोजन, आवास, स्वास्थ्य और लड़कियों की शिक्षा उपलब्ध कराई गई।

गृहमंत्री ने कहा कि देश में मौजूद अवैध घुसपैठियों को मानव अधिकार के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उनके प्रति कोई अमानवीय व्यवहार नहीं हुआ है। मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट का हाल का फैसला सात रोहिंग्या शरणार्थियों को उनके देश वापस भेजे जाने के समर्थन में आया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और मानवाधिकार किसी धर्म पर आधारित नहीं है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा की अहमियत पर भी जोर दिया।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के रजत जयंती समारोह के इस मौके पर स्मारिका के रूप में एक डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने एनएचआरसी की वेबसाइट का नया संस्करण भी जारी किया। इस मौके पर आयोजित समारोह में उपस्थित विशिष्ट लोगों में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनोज सिन्हा भी उपस्थित थे। ■

देश में प्रमुख फसलों के उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी 75 फीसदी

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधामोहन सिंह ने एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में महिला किसान दिवस समारोह में उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए 15 अक्टूबर को कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास में महिलाओं का अहम योगदान है। आर्थिक रूप से सक्रिय 80 प्रतिशत महिलाएं कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। इनमें से लगभग 33 प्रतिशत मजदूरों के तौर पर और 48 प्रतिशत स्व-नियोजित किसानों के तौर पर कार्य कर रही हैं। एनएसएसओ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 18 प्रतिशत खेतिहर परिवारों का नेतृत्व महिलाएं ही करती हैं। कृषि कार्यों के साथ साथ महिलाएं बागवानी, मछली पालन, कृषि वानिकी, पशुपालन और मधुमक्खी पालन जैसे कार्यों में भी बखूबी अपना योगदान दे रही हैं।

उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से नौ राज्यों में किये गये एक अनुसंधान से पता चला है कि प्रमुख फसलों के उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी 75 फीसदी तक रही है। बागवानी में यह आंकड़ा 79 प्रतिशत और फसल कटाई के बाद के कार्यों में 51 फीसदी तक भागीदारी ग्रामीण महिलाओं की है। इसके अलावा, पशुपालन और मछली उत्पादन में यह आंकड़ा 95 प्रतिशत तक है।

कृषि मंत्री ने बताया कि महिलाओं को कृषि की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा विभिन्न स्कीमों में महिलाओं के लिए बजट संबंधी वचनबद्धता को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों और विकास संबंधी गतिविधियों के अंतर्गत महिलाओं के लिए 30% से अधिक धनराशि का आवंटन किया गया।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कृषि महिला संसाधन केंद्र द्वारा पुरुष कार्यक्रम संचालकों की मानसिकता और व्यवहार में बदलाव लाने के लिए एक महिला संवेदनशील मॉड्यूल भी विकसित किया गया है। इसके माध्यम से वर्ष 2017-18 के दौरान 222 कार्यक्रमों के माध्यम से कुल 5645 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही 'आत्मा' कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 98.14 लाख से अधिक महिला किसानों को भी प्रशिक्षित किया जा चुका है ।

श्री सिंह ने बताया कि कृषक परिवार की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी करने के लक्ष्य, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, में भी महिलाओं की भूमिका एवं योगदान को विशेष महत्व दिया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए डॉ. दलवई की अध्यक्षता में गठित अंतर-मंत्रालय समिति ने अपनी रिपोर्ट के ग्यारहवें अध्याय में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण पर अलग से एक अध्याय लिखा है, जिसके कार्यान्वयन से महिलाएं अपने परिवार की आय वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगी। कृषि में महिलाओं की अहम भागीदारी को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषिरत महिला संस्थान, भुवनेश्वर भी कार्य कर रहा है।

उन्होंने बताया कि सहकारिता के क्षेत्र में सामूहिक क्रिया-कलापों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राज्यों/राज्य सहकारी संघों के माध्यम से भारत राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा महिलाओं के नियमित सहकारी शिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इसके तहत पिछले दो वर्षों में सहकारिता के क्षेत्र में एन.सी.यू. आई. के अंतर्गत 38.78 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। इसी प्रकार कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से 6.07 लाख महिलाएं व कौशल प्रशिक्षण के

माध्यम से 7 हज़ार महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। कुल मिलाकर 2016-17 व 2017-18 के दौरान कुल 53.34 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।

उन्होंने बताया कि किसान महिलाओं के खाद्य सुरक्षा समूहों को समर्थन देने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा संशोधित आत्मा योजना के तहत घरेलू और सामुदायिक स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु महिलाओं के खाद्य सुरक्षा समूहों को 2 समूह/प्रति ब्लॉक की दर से तथा 10,000 रुपये प्रति समूह/प्रति वर्ष की दर से वित्तीय सहायता दी जा रही है।

सम्बोधन के अंत में कृषि मंत्री ने समारोह में सम्मानित महिला कृषकों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि महिला कृषक देश को कृषि की द्वितीय हरित क्रान्ति की ओर ले जाने के साथ-साथ देश के विकास का परिदृश्य बदलने में सराहनीय योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की महिला कल्याण नीतियों और ऐसी विशेष अभिरुचियों के चलते वह दिन दूर नहीं, जब महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कन्धा मिलाकर एक सशक्त परिवार का निर्माण करेंगी। ■

ऊर्जा सुरक्षा, किफायती ऊर्जा एवं ऊर्जा निरंतरता की ओर तेजी से बढ़ते कदम: धर्मेन्द्र प्रधान

केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने 15 अक्टूबर को कहा कि ऊर्जा एक वैश्विक उद्योग है और तेल सही अर्थों में एक वैश्विक जिंस या वस्तु है। अतः इसे ध्यान में रखते हुए हमें वैश्विक ऊर्जा समुदाय के साथ अपनी सहभागिता निरंतर जारी रखनी होगी। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में आयोजित सीईआरए सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत अलग-थलग नहीं रह सकता है, क्योंकि वैश्विक नजरिए से यदि देखा जाए तो वैश्विक बाजार में हो रहे फेरबदल, व्यापक तकनीकी बदलाव, वित्तीय बाजार एवं पेपर ट्रेडिंग और ऊर्जा क्षेत्र में संक्रमण या बदलाव के आसार ऊर्जा सुरक्षा के भविष्य को नया स्वरूप प्रदान कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में किसी भी कदम को उठाते समय सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडे के तहत हासिल की गई वैश्विक आम सहमति, वर्ष 2015 में हुए 'पेरिस समझौते' और वर्ष 2017 में हैम्बर्ग में हुई जी-20 के राजनेताओं की बैठक में लिये गए निर्णयों को ध्यान में रखना होगा, जिसके तहत ऊर्जा सुरक्षा को भी ऊर्जा क्षेत्र में संक्रमण के दौर के लिए निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक माना जाता है। उन्होंने ह्यूस्टन से बाहर इस प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन किए जाने और भारत को दूसरी बार इसका आयोजन स्थल बनाए जाने के लिए आईएचएस की टीम के प्रयासों की सराहना की।

श्री प्रधान ने कहा कि भारत ने सौर ऊर्जा की दृष्टि से संपन्न 60 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की अगुवाई की है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से जुड़े सम्मेलन के एक हिस्से के रूप में दो सप्ताह पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यह उल्लेख किया था कि आईएसए विश्व में ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं के महत्वपूर्ण खंड (ब्लॉक) के रूप में ओपेक का स्थान ले सकता है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा की घटती दरों को देखते हुए हम आसानी से 'एक विश्व, एक सूर्य, एक ग्रिड' संबंधी उनके विजन को साकार कर सकते हैं।

श्री प्रधान ने कहा कि हम ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े माननीय प्रधानमंत्री के विजन 'ऊर्जा पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा, किफायती ऊर्जा एवं ऊर्जा निरंतरता सुनिश्चित करने' को साकार करने में जुट गए हैं। तेज उतार-चढ़ाव वाले वैश्विक परिदृश्य में ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और सबसे तेजी से विकासोन्मुख देश होने के नाते हम ऊर्जा के केवल एक ही स्रोत पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। श्री प्रधान ने कहा कि जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष कहा था कि सूर्य देवता के रथ में जुड़े घोड़ों की तरह भारत उपलब्ध ऊर्जा के सभी स्रोतों यथा सौर, पवन, पनबिजली, कोयला, तेल, गैस, परमाणु ऊर्जा, जैव ईंधनों इत्यादि का दोहन करेगा।

हम ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े माननीय प्रधानमंत्री के विजन 'ऊर्जा पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा, किफायती ऊर्जा एवं ऊर्जा निरंतरता सुनिश्चित करने' को साकार करने में जुट गए हैं। तेज उतार-चढ़ाव वाले वैश्विक परिदृश्य में ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और सबसे तेजी से विकासोन्मुख देश होने के नाते हम ऊर्जा के केवल एक ही स्रोत पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष कहा था कि सूर्य देवता के रथ में जुड़े घोड़ों की तरह भारत उपलब्ध ऊर्जा के सभी स्रोतों यथा सौर, पवन, पनबिजली, कोयला, तेल, गैस, परमाणु ऊर्जा, जैव ईंधनों इत्यादि का दोहन करेगा।

श्री प्रधान ने लागू किए गए विभिन्न सुधारों और पहलों की दिशा में हुई हालिया प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि सभी लोगों तक स्वच्छ रसोई ईंधन की पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत हमने 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' शुरू की है, जिसके तहत हमने तीन वर्षों की अवधि में 50 मिलियन परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा था। हमने तय अवधि से पहले ही यह उपलब्धि हासिल कर ली है और इस लक्ष्य को बढ़ाकर 80 मिलियन कर दिया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत स्वच्छ ईंधन को अपनाया जा रहा हैं और इसके साथ ही इस योजना का सकारात्मक असर ग्रामीण महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना ने 'सावधि गरीबी' के मुद्दे को सुलझाते हुए गरीब महिलाओं को सशक्त भी बनाया है और इसके साथ उन्हें अपनी मानव पूंजी में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया है। श्री प्रधान ने कहा कि वितरण के अनूठे मॉडलों, प्रौद्योगिकी के उपयोग और निर्देशित सब्सिडी की नीति के जरिए हम ऊर्जा के लिए उपभोक्ता बाजार का विस्तार करने में सक्षम साबित हुए हैं। ■

देश की तरक्की के लिए जरूरी है सरकारी खजाने की सेहत में तेजी से सुधार

बीते तीन सालों में सालाना एक करोड़ रुपये से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या बढ़ना केवल यही नहीं बताता कि कालेधन के खिलाफ सरकार की मुहिम रंग ला रही है, बल्कि यह भी प्रकट करता है कि लोगों में सरकारी तंत्र पर भरोसा बढ़ रहा है और वे अपने हिस्से का टैक्स चुकाने के लिए आगे आ रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2014-15 के मुकाबले 2017-18 में अपनी आय सालाना एक करोड़ रुपये बताने वाले व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या में 68 प्रतिशत की अच्छी-खासी वृद्धि दर्ज की गई। इसमें नोटबंदी और जीएसटी पर अमल की भी भूमिका को देखा जाना चाहिए।

हालात किस तरह बदल रहे हैं, इसे इस आंकड़े से और भी अच्छे से समझा जा सकता है कि जहां वित्त वर्ष 2013-14 में कुल 3.79 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल हुए थे, वहीं 2017-18 में उनकी संख्या बढ़कर 6.85 करोड़ हो गई। चूंकि इस वित्त वर्ष आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले नए करदाताओं का आंकड़ा सवा करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है इसलिए यह कहा जा सकता है कि एक अच्छा सिलसिला कायम हो गया है। यह सिलसिला केवल सरकारी खजाने की सेहत सुधारने वाला ही नहीं, देश की प्रगति में योगदान देने वाला भी है।

यह सही है कि सवा सौ करोड़ से अधिक आबादी अथवा करीब 25 करोड़ परिवारों वाले इस देश में आयकर दाताओं की कुल संख्या 6.85 करोड़ कोई बहुत अधिक नहीं, लेकिन इससे बेहतर और कुछ नहीं कि सक्षम लोग आयकर के दायरे में आना उचित समझ रहे हैं।

जहां वित्त वर्ष 2013-14 में कुल 3.79 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल हुए थे, वहीं 2017-18 में उनकी संख्या बढ़कर 6.85 करोड़ हो गई। चूंकि इस वित्त वर्ष आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले नए करदाताओं का आंकड़ा सवा करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है इसलिए यह कहा जा सकता है कि एक अच्छा सिलसिला कायम हो गया है। यह सिलसिला केवल सरकारी खजाने की सेहत सुधारने वाला ही नहीं, देश की प्रगति में योगदान देने वाला भी है।

भले ही ऐसा कोई आंकड़ा उपलब्ध न हो कि कितने लोग सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के चलते इस दायरे में आ रहे हैं और कितने स्वेच्छा से, लेकिन जो भी स्वतः आ रहे हैं वे साधुवाद के पात्र हैं।

देश में आयकर दाता बढ़ने के लिए यह भी आवश्यक है कि समृद्धि का विस्तार से तेजी हो और ऐसा तब होगा जब सभी समर्थ लोग टैक्स चुकाएंगे। यह स्वागत योग्य है कि सरकार का आधे से ज्यादा खजाना आयकर विभाग भर रहा है। जब सरकार के खजाने में पर्याप्त पैसा होगा तभी वह जन कल्याण के साथ विकास की योजनाओं पर अमल कर सकेगी। ऐसी ही योजनाएं निर्धन तबके को गरीबी रेखा से ऊपर लाती हैं और समय के साथ इस तबके के कुछ लोग भविष्य के आयकर दाता बनते हैं।

चूंकि ऐसे आंकड़े सामने आ चुके हैं कि बीते एक दशक में अपने देश में करीब 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल आए हैं। इसलिए इस शिकायत के लिए कोई गुंजाइश नहीं कि सरकारें आखिर सरकारी खजाने का करती क्या हैं? वे राष्ट्र को सक्षम-समर्थ बनाने के उपाय करती हैं और उन्हें आसानी तब होती है जब आम लोग आर्थिक नियम-कानूनों का भी स्वेच्छा से पालन करते हैं। यह एक हकीकत है कि जिन देशों के आम लोग नियम-कानूनों के प्रति जितनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं वे उतनी ही तेजी से आगे बढ़ते हैं। भारत को तेजी से आगे बढ़ते हुए विकसित देशों की कतार में आना है तो तमाम अन्य बातों के साथ यह भी आवश्यक है कि जो समर्थ हैं वे टैक्स चुकाएं। ■

(दैनिक जागरण की संपादकीय टिप्पणी)

'मिजोरम की जनता बदलाव चाहती है'

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 17 अक्टूबर को मिजोरम की कांग्रेस सरकार को 'भ्रष्ट' बताते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार राज्य के लोगों को अपनी सेवाएं देने में विफल रही। आइजोल के आर देंगथुआमा इंडोर स्टेडियम में एक रैली के दौरान श्री शाह ने राज्य के मुख्यमंत्री लाल थनहवला पर 'भ्रष्ट सरकार और वंशवादी शासन' चलाने को लेकर प्रहार किया।

श्री शाह ने कहा कि कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखकर उन्हें यह कहने में गुरेज नहीं कि कांग्रेस की करारी हार होने जा रही है। राज्य की जनता कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार से तंग है। उन्होंने कांग्रेस को सभी तरह के भ्रष्टाचारों का जनक बताया और इसके साथ ही विकास के लिए भाजपा को वोट देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मिजोरम में कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कई विकास योजनाओं को लागू नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा मिजोरम में सरकार बनाती है तो केंद्र सरकार के 100 से ज्यादा कार्यक्रमों को लागू किया जाएगा।

मिजोरम में कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कई विकास योजनाओं को लागू नहीं किया है। राज्य की जनता कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार से तंग है।

श्री शाह ने कहा कि इस बार मिजोरम नया इतिहास लिखेगा। मिजोरम की जनता बदलाव चाहती है और उन्हें साफ दिखाई दे रहा है कि भाजपा जीत रही है। उन्होंने कहा कि देश के कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और उम्मीद है कि राज्य की जनता कांग्रेस सरकार को इस बार मौका नहीं देगी।

श्री शाह ने आइजोल में भाजपा के राज्य कार्यालय अटल भवन का भी उद्घाटन किया।

गौरतलब है कि भाजपा ने 2016 में एनईडीए नाम का राजनीतिक गठबंधन किया था। इसमें नगा पीपल्स फ्रंट, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट शामिल थे। श्री शाह ने कहा कि भाजपा मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

विदित हो कि मिजोरम में 28 नवंबर को एक चरण में चुनाव होगा। चुनाव परिणाम की घोषणा 11 दिसंबर को अन्य चार राज्यों के चुनाव परिणामों के साथ की जाएगी। ■

'जनता से किए गए वादों को पूरा करने में असफल रही है तेलंगाना सरकार'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 10 अक्टूबर को आंबेडकर ग्राउंड करीमनगर में विशाल जनसभा को संबोधित किया और तेलंगाना की टीआरएस सरकार के वादाखिलाफियों और कांग्रेस की यूपीए सरकार द्वारा तेलंगाना की जनता के साथ किये गए अन्याय को लेकर टीआरएस और कांग्रेस पार्टी पर जमकर प्रहार किया।

उन्होंने कहा कि अप्रैल-मई में तेलंगाना के विधानसभा चुनाव होने ही थे, लेकिन समय से पहले चुनाव कराकर केसीआर और टीआरएस ने एक छोटे राज्य को दो बड़े चुनावों का खर्च सहने को विवश कर दिया है। तेलंगाना की जनता पर इतना खर्च क्यों थोपा गया? इसका क्या कारण है? उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि सिर्फ और सिर्फ निहित राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए ही केसीआर और टीआरएस ने करोड़ों रुपये का अतिरिक्त खर्च तेलंगाना की जनता पर थोपा है। केसीआर को डर था कि उस समय चुनाव होने पर श्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता के आगे वे टिक नहीं पाएंगे।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि तेलंगाना में तेलुगु अस्मिता और तेलुगु गौरव की बात करने वाले लोगों ने प्रतिवर्ष 17 सितंबर को आयोजित होने वाली 'हैदराबाद मुक्ति दिवस' का उत्सव बंद कर दिया। तेलुगु अस्मिता पर इससे बड़ा आघात कुछ और हो नहीं सकता। वोट बैंक और तुष्टिकरण के कारण ऐसा किया गया। क्या हम आज तेलंगाना को आज के रजाकारों के हाथ में सौंपना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जनता को तय करना है कि क्या उन्हें ऐसी सरकार चाहिए जो तेलुगु अस्मिता और तेलुगु संस्कृति पर कुठाराघात कर रही है?

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी तेलगु देशम के साथ मिलकर टीआरएस का विकल्प बनना चाहती है, लेकिन ये दोनों दल कभी भी रजाकारों का विरोध नहीं कर सकते हैं। विफल टीआरएस का एकमात्र विकल्प भारतीय जनता पार्टी ही है न कि भ्रष्ट कांग्रेस-तेलगुदेशम का गठबंधन। आज भी तेलांगना की जनता को याद है कि किस तरह से यहां के महान सपूत और कांग्रेस पार्टी ने अपने ही नेता पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव के साथ क्या व्यवहार किया था। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं करने दिया और न ही कांग्रेस कार्यालय श्रद्धांजलि देने के लिए खोला गया।

श्री शाह ने कहा कि टीआरएस और कांग्रेस पार्टी परिवारवाद, वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, वह तेलंगाना का विकास नहीं कर सकती। परिवारवाद लोकतंत्र की मूल परिकल्पना पर आघात करती है, लोकतंत्र को निर्बल बनाती है, लेकिन तेलंगाना में केवल और केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए विधान सभा चुनाव समय से पूर्व ही राज्य की जनता पर थोपा गया है।

भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि आखिर कांग्रेस पार्टी किस अधिकार से तेलंगाना की जनता के पास वोट मांगने जायेगी? जबकि, तेलंगाना और तेलंगाना की जनता के साथ अन्याय करने में कांग्रेस पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी भेदभाव के संघीय ढांचे की भावना को मजबूत करते हुए तेलंगाना को विकास के लिए पर्याप्त धनराशि मुहैया कराई है।

श्री शाह ने कहा कि टीआरएस सरकार पिछले विधानसभा चुनाव के समय तेलंगाना की जनता से किये गए वादों को पूरा करने में असफल रही है। तेलंगाना आंदोलन के 1200 शहीदों के शोकग्रस्त

परिवारों को रोजगार देने का वादा भी आधा-अधूरा पड़ा है। शिक्षकों एवं प्रोफेसरों की नियुक्ति भी अटकी पड़ी है। सरकारी स्कूलों के लिए किये गए वादे भी पूरे नहीं हुए। सिंचाई की एक भी परियोजना की शुरुआत नहीं की गई । जिला मुख्यालयों पर 100 बेड और मंडल मुख्यालयों पर 30 बेड के अस्पताल का निर्माण करने का वादा किया गया था, लेकिन इस पर कोई भी काम नहीं हुआ है। गरीबों के लिए दो लाख डबल बेड रूम वाले घरों का निर्माण कराने की घोषणा की गई थी, लेकिन इसमें इसे कितने डबल बेड रूम बने, किसी को इसका पता नहीं है। यहां तक कि केंद्र सरकार से आवास के लिए दी गयी राशि भी खर्च नहीं की गयी।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टीआरएस सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि नए घोषणापत्र में ये वादे फिर से शामिल किये जायेंगे या नहीं, इस पर टीआरएस को स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीआरएस ने पिछले चुनाव के समय जो भी वादे तेलंगाना की जनता से किये थे, उसमें से एक को भी पूरा नहीं किया गया है। उस समय दलित मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

श्री शाह ने कहा कि साढ़े चार सालों में तेलंगाना में किसानों की स्थिति बद से बदतर हुई। एक आंकड़े का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अबतक यहां साढ़े चार हजार किसान आत्महत्या करने को विवश हुए हैं, राज्य की जनता इसका हिसाब मांग रही है। वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश भर के किसानों को उनकी फसल पर लागत मूल्य का डेढ़ गुना या इससे भी ज्यादा समर्थन मूल्य दे रही है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने 'आयुष्मान भारत' योजना के तहत देश के 10 करोड़ परिवारों अर्थात् लगभग 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने का निर्णय लिया है जिससे स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ने में देश के गरीबों को आसानी होगी, लेकिन तेलंगाना सरकार ने इसे लागू नहीं कर यहां की जनता को इस लाभ से वंचित कर घोर अन्याय किया है।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने फसल की क्षति से किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा लेकर आई, लेकिन तेलंगाना में केवल 15% किसान ही इस योजना का लाभ उठा पाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को राज्य में जानबूझ कर लटकाया जा रहा है। तेलंगाना सरकार मिशन इन्द्रधनुष, एनटीपीसी और मलेरिया के फंड का केवल 38% ही उपयोग कर पाई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में चार साल पहले तीन फूड पार्कों के लिए केंद्र सरकार ने 165 करोड़ आवंटित किये, लेकिन अब तक ये फूड पार्क पूरे नहीं हुए और कृषि बाजारों को जोड़ने की योजना भी तेलंगाना में अधूरी है। मोदी सरकार की लोक-कल्याणकारी योजनाओं को जानबूझ कर तेलंगाना सरकार द्वारा लटका कर रखा जा रहा है, ताकि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की योजनायें राज्य की आम जनता तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग में ग्राम पंचायतों के लिए जो राशि आवंटित हुई है, वह भी गांवों तक अभी नहीं पहुंची है जिससे गांवों का विकास सही से हो नहीं पाया है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र में जब सोनिया-मनमोहन की कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार थी, तब 13वें वित्त आयोग में तेलंगाना को शेयर इन सेन्ट्रल टैक्स, केन्द्रीय अनुदान सहायता, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, आपदा राहत फंड और लोकल बॉडीज ग्रांट के तौर पर केवल 16,597 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी जबकि मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग में राज्य के लिए इन पांच सेक्टरों में 1,15,605 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। तेलंगाना में केंद्र सरकार की ओर से एम्स, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, श्रीकोंडा लक्ष्मण तेलंगाना बागवानी विश्वविद्यालय प्रो जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और पी वी नरसिम्हा राव वेटरनिटी यूनिवर्सिटी दी गई है। इसके अलावा कॉटन रिसर्च सेंटर और स्पाइस रिसर्च सेंटर को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल इन हैदराबाद और सेंटर फॉर इनोवेशन फॉर डिफेन्स एक्सिलेंस, हैदराबाद को मान्यता दी गई है।

श्री शाह ने बताया कि तेलंगाना में मुद्रा बैंक के 18 लाख लाभार्थियों को 15 हजार करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है। स्मार्ट सिटी के लिए 124 करोड़ रुपये, वारंगल हृदय योजना के लिए 40 करोड़ रुपये, अमृत मिशन के लिए 833 करोड़ रुपये, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन हैदराबाद के लिए 158 करोड़ रुपये, मेट्रो के लिए 661 करोड़ रुपये, अलग-अलग रेलवे परियोजनाओं के लिए 19,902 करोड़ रुपये, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के लिए 1150 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना के 145 प्रोजेक्ट के लिए 1221 करोड़ रुपये, 9 पिछड़े जिले के विकास के लिए 900 करोड़ रुपये, सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 40800 करोड़ रुपये, महिला एवं बाल विकास के लिए 1055 करोड़ रुपये, कृषि सिंचाई एवं पशुधन विकास के लिए 915 करोड़ रुपये, उर्वरक प्लांट के लिए 5200 करोड़ रुपये, एम्स तेलंगाना के लिए 1200 करोड़ रुपये, सर्व शिक्षा अभियान के लिए 1353 करोड़ रुपये और नक्सल प्रभावित जिलों के लिए 400 करोड़ रुपये अलग से दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं में तेलंगाना को 115000 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए गए हैं। इस तरह से तेलंगाना को केंद्र की मोदी सरकार की ओर से कुल 2,30,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जो कांग्रेस सरकार के दौरान 13वें वित्त आयोग में दी गई राशि से लगभग 20 गुना अधिक है।

हम पूरी मजबूती के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में तेलंगाना के विकास के लिए गांव-गांव जाने के लिए तैयार हैं। हमारे कार्यकर्ता राज्य के हर बूथ तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने तेलंगाना के लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य को पूर्ण विकसित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तथा 2019 के आम चुनाव में केंद्र में सर्वप्रिय नेता श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का संकल्प लें।

तेलंगाना की जनता को भरोसा दिलाते हुए श्री शाह ने कहा कि हम पूरी मजबूती के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में तेलंगाना के विकास के लिए गांव-गांव जाने के लिए तैयार हैं। हमारे कार्यकर्ता राज्य के हर बूथ तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने तेलंगाना के लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य को पूर्ण विकसित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तथा 2019 के आम चुनाव में केंद्र में सर्वप्रिय नेता श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का संकल्प लें।

इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने हैदराबाद में महाराज अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया।

राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल थी आजाद हिंद सरकार: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित आज़ाद हिंद सरकार के गठन की 75वीं वर्षगांठ की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में 21 अक्टूबर को लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पट्टिका का अनावरण किया। इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मृति कार्यक्रम में संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. महेश शर्मा, नेताजी के भतीजे चंद्र कुमार बोस, श्री ललती राम, आईएनए के वयोवृद्ध सेनानी और ब्रिगेडियर आर.एस चिक्कारा भी शामिल हुए।

प्रधानमंत्री ने आज़ाद हिंद सरकार के गठन की 75वीं वर्षगांठ के गौरवान्वित अवसर पर देश को बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज़ाद हिंद सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा निर्धारित मजबूत अविभाजित भारत के विज़न का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कहा कि आजाद हिंद सरकार राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल थी, यहां तक कि उसने अपने बैंक, मुद्रा और टिकट भी शुरू कर दिये थे।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि नेताजी एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, जिन्होंने शक्तिशाली औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ने के लिए भारतीयों को एकजुट किया। उन्होंनें यह भी कहा कि नेताजी ने युवा अवस्था में ही देशभक्ति का प्रदर्शन कर दिया था। उनकी यह भावना अपनी मां को लिखे उनके पत्रों में दिखाई देती थी।

श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि नेताजी न केवल भारतीयों के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे, बल्कि वे दुनिया भर में उन लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत थे, जो अपने देशों में आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लड़ रहे थे। इस संदर्भ में उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला का उल्लेख किया कि वे किस प्रकार नेताजी से प्रेरित थे।

राष्ट्र को यह स्मरण कराते हुए कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा कल्पना किए गए नये भारत का निर्माण करने से पहले उन्हें लंबा रास्ता तय करना है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से अनुरोध किया कि वे नेताजी से प्रेरणा लेकर राष्ट्र के विकास की दिशा में काम करें। उन्होंने कहा कि भारत ने अनेक बलिदानों के बाद आजादी हासिल की है और यह नागरिकों का कर्तव्य है कि वे अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखें।

प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के गठन के माध्यम से सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए समान अवसर प्रदान करने की नींव रखी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सच्चे अर्थों में इस विरासत को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने यह भी दोहराया कि महिलाओं को सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

इससे पहले स्वागत भाषण देते हुए संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. महेश शर्मा ने कहा कि राष्ट्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सलाम करता है, जिनका बलिदान और नेतृत्व हमारी युवा पीढ़ी का लगातार मार्गदर्शन कर रहा है। उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री के सक्षम नेतृत्व को धन्यवाद दिया। ■

सुभाष चंद्र बोस के नाम पर पुलिसकर्मियों को मिलेगा पुरस्कार

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21 अक्टूबर को ऐलान किया कि आपदा के दौरान राहत एवं बचाव अभियान में बेहतरीन काम करने वाले पुलिसकर्मी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक सालाना राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा।

21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारत की पहली स्वतंत्र सरकार 'आजाद हिंद सरकार' के गठन की घोषणा के 75 साल पूरे होने के मौके पर मोदी ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हर साल नेताजी के जन्मदिन 23 जनवरी को इस अवॉर्ड की घोषणा की जाएगी। श्री मोदी ने कहा, ''इस साल से हम ऐसे पुलिसकर्मी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक अवॉर्ड देंगे, जो किसी आपदा के दौरान लोगों को राहत एवं बचाव के लिए बेहतरीन काम करते हैं।"

'भाजपा सरकार ने तुष्टिकरण की राजनीति की जगह पॉलिटिक्स ऑफ़ परफॉरमेंस की राजनीति की'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 13 अक्टूबर को मेडिकल कॉलेज सभागार, रायपुर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया और उन बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की कि आखिर क्यों छत्तीसगढ़ में पुनः भारतीय जनता पार्टी की श्री रमण सिंह सरकार की आवश्यकता है।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के साढ़े चार सालों के दौरान देश में हुए बदलावों को चार महत्वपूर्ण मानकों के आधार पर समझने की जरूरत है।

पहलाः राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के सोचने के स्केल को ऊपर उठाने का अभूतपूर्व प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि पहले योजनायें बनती थी कि इतने लोगों को गैस देना, घर देना है, इतने गांवों में बिजली पहुंचानी है जबकि मोदी सरकार का लक्ष्य है कि हर घर में बिजली हो, गैस सिलिंडर हो, शौचालय हो, हर गरीब के पास अपनी छत हो, हर गांव में पक्की सड़कें हो और शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाएं हो।

दूसराः श्री शाह ने कहा कि पहले कांग्रेस पार्टी सरकार चलाने के लिए सत्ता में आती थी, आज देश बदलने और जनता की सेवा के संकल्प के साथ मोदी सरकार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आने के उद्देश्य को बदलने का कार्य किया है। उन्होंने कई लोक-कल्याणकारी योजनाओं का उद्धरण देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने पिछले चार सालों में 31 करोड़ से अधिक लोगों के जन-धन खाते खोले। साढ़े 5 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस सिलिंडर दिए, साढ़े सात करोड़ से अधिक करोड़ शौचालयों का निर्माण कराया। दो करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई, 18 करोड़ छोटे गरीब बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया एवं दो करोड़ घरों का निर्माण कराया है। उन्होंने कहा कि हमने आजादी के 70 सालों तक किसानों की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए फसलों के समर्थन मूल्य को लागत मूल्य का डेढ़ गुना करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देशवासियों के स्वास्थ्य की चिंता को ध्यान में रखते हुए 'आयुष्मान भारत' योजना लेकर आये हैं, जिसके तहत देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को अर्थात् 50 करोड़ से अधिक लोगों को पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष तक की मुफ्त बीमा प्रदान की जा रही है।

तीसराः भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार ने लोगों को अच्छे लगने वाले फैसले की जगह ऐसे फैसले लिए जो लोगों के लिए अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति की जगह पॉलिटिक्स ऑफ़ परफॉरमेंस के राजनीति की शुरुआत की और सभी पॉलिटिकल डिबेट को विकास के मुद्दे से जोड़ा। उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स ऑफ़ परफॉरमेंस की नीति के कारण आज भारत विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के साथ-साथ विश्व की छठी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित है। बहुत जल्द ही हम पांचवें स्थान पर आने वाले हैं।

चौथाः श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्र सरकार को कई प्रकार के अंतर्द्वंदों से भी बाहर निकालने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 70 साल के इतिहास में जितनी भी सरकारें आई, वह कई तरह के द्वंद्वों में फंसी रहती थी कि सरकार किसानों का विकास करेगी या उद्योगों को बढ़ावा देगी। गांवों का विकास करेगी या

शहरों का विकास करेगी, रिफॉर्म्स पर ध्यान देगी या लोक-कल्याण राज्य की स्थापना के लिए काम करेगी, विदेश नीति को तवज्जो देगी या रक्षा नीति को। सरकार को ब्यूरोक्रेट्स चलाएंगे या फिर जन-प्रतिनिधि। लेकिन मोदी सरकार ने चार सालों में बिना किसी द्वंद्व में फंसे यह सिद्ध कर दिया है कि एक साथ किसानों का भी विकास हो सकता है तो उद्योगों का भी। साथ-साथ गांवों का कायाकल्प भी किया जा सकता है और शहरों के इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया जा सकता है, रिफॉर्म्स भी हो सकते हैं और जन-कल्याण के कार्य भी बखूबी अंजाम दिए जा सकते हैं। साथ ही, विदेश नीति और रक्षा नीति पर समान रूप से काम किया जा सकता है।

बुद्धिजीवियों से अपील करते हुए श्री शाह ने कहा कि लोकतंत्र में दिशा-विहीन होकर मतदान करना घातक सिद्ध हो सकता है इसलिए आप जनता को जागरूक करें और छत्तीसगढ़ को समृद्ध राज्य बनाने के लिए एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की रमण सिंह सरकार का गठन सुनिश्चित करें। ■

प्रधानमंत्री को मिला सियोल शांति पुरस्कार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास को गति देकर भारत में लोगों के जीवन स्तर को सुधारने तथा भ्रष्टाचार निरोधक उपायों और सामाजिक एकता के प्रयासों के जरिए देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए 2018 के सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सियोल शांति पुरस्कार समिति ने यह सम्मान प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री के नाम का चयन किया है।

समिति ने कहा है कि वह भारत सहित वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास में श्री मोदी के योगदान और गरीब और अमीर के बीच आर्थिक और सामाजिक विषमताओं की खाई पाटने में 'मोदीनॉमिक्स' के महत्व को स्वीकार करती है। समिति ने विमुद्रीकरण और भ्रष्टाचार निरोधक उपायों के जरिए सरकारी तंत्र को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए कदमों की भी सराहना की है। समिति ने 'मोदी सिद्धांत' और 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के माध्यम से दुनिया भर के देशों के साथ एक सक्रिय विदेशी नीति के जरिए क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के प्रति उनके योगदान को भी स्वीकार किया है। श्री मोदी यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले 14वें व्यक्ति हैं।

कोरिया गणराज्य के साथ भारत की मजबूत भागीदारी के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री ने इस प्रतिष्ठित सम्मान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे स्वीकार किया है। आपस में सहमति के अनुसार किसी निर्धारित दिन यह पुरस्कार श्री मोदी को सियोल शांति पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा दिया जाएगा।

पृष्ठभूमि : सियोल शांति पुरस्कार की शुरुआत 1990 में कोरिया

गणराज्य में 24वें ओलंपिक खेलों के सफल आयोजन के उपलक्ष्य में की गई थी। इन खेलों में दुनिया भर के 160 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लेते हुए सद्भाव, मित्रता, शांति और आपसी मेल-मिलाप के विश्वव्यापी माहौल का निर्माण किया। यह पुरस्कार कोरियाई लोगों को देश और दुनिया में शांति बनाए रखने की इच्छा का प्रतीक है।

यह पुरस्कार मानवता के कल्याण और विश्व शांति के लिए योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रत्येक दो वर्ष में एक बार दिया जाता है। इस पुरस्कार के पिछले विजेताओं में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान, जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल और डॉक्टर्स विदाउट बॉडर्स तथा ऑक्सफैम जैसी प्रसिद्ध हस्तियों सहित अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। इस पुरस्कार के लिए प्रधानमंत्री के नाम का चयन 1300 से अधिक उम्मीदवारों के बीच किया गया है। चयन समिति ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को इस पुरस्कार के लिए 'सर्वश्रेष्ठ' उम्मीदवार माना है। ■

सियोल शांति पुरस्कार प्रधानमंत्री के वैश्विक सहयोग बढ़ाने के प्रयासों का सम्मान है: अमित शाह

प्रधानमंत्री को सियोल शांति सम्मान के लिए चुने जाने के लिए बधाई देते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 24 अक्टूबर को कहा कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर दुनिया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकार रही है।

श्री शाह ने कहा कि दक्षिण कोरिया के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय सियोल पीस प्राइज कल्चरल फाउंडेशन द्वारा भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के विकास में योगदान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित करना सवा सौ करोड़ देशवासियों के लिए गर्व एवं खुशी का क्षण है। अपने सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक अभियानों से अखिल विश्व को प्रभावित करने और प्रभावी संदेश देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के माध्यम से गौरवान्वित करने का एक और अवसर देने के लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वैश्विक शांति, मानव विकास में सुधार, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार को समाप्त करने और सामाजिक एकीकरण एवं सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से भारत में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने की दिशा में

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अमूल्य योगदान के लिए सियोल पीस प्राइज कल्चरल फाउंडेशन ने उन्हें सम्मानित किया है। यह पुरस्कार प्रधानमंत्री जी के वैश्विक सहयोग एवं वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ाने के प्रयासों का सम्मान है।

श्री शाह ने कहा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन ने अमीरों और गरीबों के बीच सामाजिक और आर्थिक खाई को कम करने के लिए 'मोदीनॉमिक्स' की प्रशंसा की है जिसकी अवधारणा ही समाज के सभी वर्गों के लिए समानता और सशक्तिकरण की भावना को आगे बढ़ाना है। इसके अलावा, पुरस्कार कमिटी ने 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' सहित प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की साहसिक, निर्णायक और अभिनव विदेश नीति की भी सराहना की गई है।

उन्होंने कहा कि पुरस्कार कमिटी ने प्रधानमंत्री जी द्वारा भ्रष्टाचार रोकने और नोटबंदी जैसे फैसलों की तारीफ की है। सक्रिय विदेश नीति के जरिए क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए किए गए प्रयासों के लिए कमिटी ने 'मोदी डॉक्ट्रिन' को भी सराहा है।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि सियोल पीस प्राइज कल्चरल फाउंडेशन 12 सदस्यीय कमिटी ने दुनिया भर के 100 से ज्यादा प्रबल दावेदारों में से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को चुना है। पुरस्कार के दावेदारों में मौजूदा और पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, राजनेता, उद्योगपति, धार्मिक नेता, विद्वान, पत्रकार, कलाकर, ऐथलीट एवं कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल थे। पुरस्कार कमिटी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को 'पर्फेक्ट कैंडिडेट' माना है जो अपने-आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वे सियोल शांति पुरस्कार पाने वाले 14वें विजेता होंगे।

उन्होंने कहा कि सियोल शांति पुरस्कार सबसे स्थापित और महत्वपूर्ण वैश्विक पुरस्कारों में से एक माना जाता है, जिनके पिछले पुरस्कार विजेताओं में पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव, कई शीर्ष विश्व नेता, शीर्ष नीति निर्माता और संगठन शामिल हैं जो कई क्षेत्रों में बड़े सामाजिक परिवर्तनों के संवाहक रहे हैं। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वालों में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रहे कोफी अन्नान, मौजूदा सचिव बान की मून, नोबेल शांति पुरस्तार विजेता डेनिस मुक्वेग और ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जुआन अंटोनियो जैसे लोग शामिल हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को हाल ही में तीन अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण

पुरस्कार 'चैंपियंस ऑफ द अर्थ' अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था। दिल्ली में एक विशेष समारोह में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने श्री मोदी को यह अवॉर्ड दिया था। श्री मोदी को यह सम्मान इंटरनेशनल सोलर अलायंस और पर्यावरण के मोर्चे पर कई महत्वपूर्ण कामों के लिए दिया गया था।

उन्होंने कहा कि इससे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानुल्ला खान अवॉर्ड, सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'द किंग अब्दुल्लाजीज साश' अवार्ड और फिलिस्तीन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ग्रैंड कॉलर' सम्मान से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। ■

कमल संदेश अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

लॉग इन करें:

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

मोदी सरकार 'शून्य भुखमरी' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरतः राधामोहन सिंह

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधामोहन सिंह ने एनएएससी कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली में विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर 16 अक्टूबर को बताया कि इस वर्ष विश्व खाद्य दिवस मनाने का उद्देश्य वर्ष 2030 तक 'शून्य भुखमरी (जीरो हंगर)' वाली दुनिया बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना है। मोदी सरकार भी 'शून्य भुखमरी' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर चरणबद्ध ढंग से कार्य कर रही है।

उन्होंने बताया कि भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने व खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा विकसित तकनीकों और हमारे किसान भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। वर्ष 2017-18 में चौथे अग्रिम आकलन के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन 284.83 मिलियन टन है, जो वर्ष 2013-14 में हासिल उत्पादन (265.04 मिलियन टन) के मुकाबले लगभग 20 मिलियन टन ज्यादा है। वर्ष 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन 277.35 मिलियन टन था जो वर्ष 2017-18 में चौथे अग्रिम आकलन के अनुसार बढ़कर 307 मिलियन टन हो गया और यह वर्ष 2013-14 में हासिल उत्पादन के मुकाबले में लगभग 30 मिलियन टन ज्यादा है। बागवानी उत्पादन में आज भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है।

वर्ष 2015-16 में दलहन फसलों का उत्पादन 16.25 मिलियन टन था, जो वर्ष 2017-18 में चौथे अग्रिम आकलन के अनुसार बढ़कर 25.23 मिलियन टन हो गया और जो वर्ष 2013-14 में हासिल उत्पादन के मुकाबले लगभग 9 मिलियन टन ज्यादा है।

उन्होंने बताया कि कृषि उत्पादन बढ़ाने में उन्नत किस्मों, तकनीकों और बीजों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वर्ष 2010 से वर्ष 2014 तक की अवधि में जहां 448 किस्में खेती के लिए जारी की गईं थीं, वहीं वर्ष 2014 से वर्ष 2018 तक की चार साल की अवधि में 795 उन्नत किस्मों को खेती के लिए जारी किया गया, जो संख्या में लगभग दोगुनी हैं। प्रजनक बीजों के मामले में वर्ष 2013-14 में जहां मांग व उत्पादन क्रमशः 8479 टन एवं 8927 टन रहा, वहीं 2016-17 में यह आंकड़ा क्रमशः 10405 टन एवं 12265 टन तक पहुंच गया।

श्री सिंह के अनुसार पहले उत्पादन पर कहीं अधिक बल दिया जाता था, मगर खाद्य पदार्थों (फूड) में वृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती थी, जिसका असर हमारी 60 प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या पर सीधे तौर पर पड़ता था और इससे छिपी हुई भुखमरी की नौबत आती थी। कुपोषण का निवारण करने के लिए पिछले साढ़े चार सालों में आईसीएआर ने पहली बार फसलों की ऐसी 20 किस्मों का विकास किया, जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा सामान्य से काफी अधिक है। कृषि का विविधीकरण करने के लिए 'राष्ट्रीय बाजरा मिशन' प्रारंभ करने के साथ एकीकृत खेती पर जोर दिया गया।

दो दिवसीय कृषि-स्टार्टअप एवं उद्यमिता कॉन्क्लेव में उपस्थित कृषि उद्यमियों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि कृषि-स्टार्टअप के लिए देश में माहौल बनाने हेतु सरकार ने स्टार्टअप एवं स्टैंडअप कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें नये युवकों को उद्यम स्थापित करने के लिए उचित सहायता एवं माहौल प्रदान करने का प्रयास किया गया।

इसी परिप्रेक्ष्य में स्किल इंडिया योजना भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर शुरू की, जिसमें सभी क्षेत्रों में कौशल विकास का कार्यक्रम देशव्यापी रूप में शुरू किया गया। आंकड़ों के अनुसार कृषि क्षेत्र को 22 लाख कुशल युवकों की आवश्यकता है, जिसके लिए आईसीएआर एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों के सहयोग से कौशल विकास से जुड़ा प्रशिक्षण विभिन्न रोजगारपरक क्षेत्रों में दिया जा रहा है। देश में मोदी सरकार ने कौशल विकास एवं स्टार्टअप के जरिए नये-नये उद्यमियों को विकसित करने का काम किया है। यह उसी का नतीजा है कि आज हम यहां विश्व खाद्य दिवस पर इन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं।

देश में खाद्यान्न उत्पादन में नए रिकॉर्ड बनाए गये हैं, परंतु मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) बनाने की तरफ सरकार बहुत तेजी से कार्य कर रही है और इसलिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत की गई है। उद्यमी युवक एवं किसान इसके अंतर्गत प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन से जुड़ी इकाइयां स्थापित कर पा रहे हैं। देश के युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से 'आर्या' नामक परियोजना संचालित की जा रही है और 'फार्मर फर्स्ट' कार्यक्रम भी इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

स्नातक स्तर पर युवाओं में कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए इंटर्नशिप देने के लिए 'अभ्यास' नामक योजना प्रारंभ की गई है, ताकि जब युवक बी.एस.सी. एग्रीकल्चर की डिग्री प्राप्त कर बाहर निकलें तो अपनी कंपनी स्थापित करने में सक्षम हो सकें। बीज एवं पौध के उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण एवं फसल कटाई उपरांत प्रबंधन, पशु चिकित्सा, कृषि मशीनरी, पोल्ट्री, मछली उत्पादन, जैविक उत्पाद के क्षेत्र में स्टार्टअप की अपार संभावनायें हैं।

सम्बोधन के आखिर में कृषि मंत्री ने कहा कि हम सभी यहां एक बार पुनः कृषि और किसानों की बेहतरी के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। उन्होंने इस सम्मेलन में भाग लेने वाले कृषि उद्यमियों और कृषि स्टार्ट-अप, किसानों एवं वैज्ञानिकों का धन्यवाद किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि विश्व खाद्य दिवस के पावन अवसर पर प्रारंभ होने वाले इस दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान विचार मंथन से कृषि क्षेत्र और किसानों की बेहतरी का मार्ग प्रशस्त होगा जिसके लिए हम सभी संकल्पबद्ध हैं। ■

'मोदी सरकार महिला सशक्तीकरण को समर्पित'

भाजपा की आधारस्तंभ नेता स्वर्गीय राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जन्मशताब्दी पर आयोजित महिला सशक्तीकरण दौड़ 16 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचकर समाप्त हुई। तालकटोरा इनडोर स्टेडियम में आयोजित समापन समारोह में प्रत्येक बूथ पर महिला कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने का संकल्प लिया गया। विदित हो कि 12 अक्टूबर को ग्वालियर से महिला सशक्तीकरण दौड़ शुरू हुई थी।

समापन समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल ने कहा कि भाजपा और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार महिला सशक्तीकरण को समर्पित है। केंद्र और भाजपा शासित राज्य सरकारें मिलकर महिला सशक्तीकरण के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। सभी पुरुषों को महिलाओं का सदैव सम्मान करना चाहिए, तभी महिला सशक्तीकरण पूर्ण रूप से सफल होगा।

केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने कहा कि राजमाता को सच्ची श्रद्धाजलि तब होगी, जब हर बूथ स्तर पर 10 बहनें संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को सुरक्षित करने के लिए राजमाता के बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा।

दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी ने कहा कि

राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने महिला सशक्तीकरण के लिए बहुत काम किया। उन्होंने कांग्रेस की गलत नीतियों का विरोध किया, इसलिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उन्हें प्रताड़ित किया। ग्वालियर से लेकर दिल्ली तक की यह दौड़ राजमाता के आदर्शों की प्रेरणा का ही परिणाम है। नई दिल्ली की सांसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत की शुरुआत राजमाता ने की थी। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती विजय रहाटकर ने कहा कि यह कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अनूठी पहल है। प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती पूनम पराशर झा ने मंच संचालन किया। ■

पुस्तक चर्चा

राष्ट्रवादी पत्रकारिता के शिखर पुरुष थे अटल बिहारी वाजपेयी

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक राजनीतिज्ञ, कवि और पत्रकार थे। अटल जी राजनेता और कवि दोनों के रूप में आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, लेकिन अटल जी राजनेता और कवि के साथ-साथ राष्ट्रवादी पत्रकारिता के शिखर पुरुष भी थे। राजनेता बनने से पहले अटल जी एक पत्रकार थे। उन्होंने राष्ट्रवादी पत्रकारिता को बढ़ावा देने और पत्रकारों की आवाज बुलंद करने में अपना खास योगदान दिया था। अटल जी के जीवन पर कई किताबें लिखी गई हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी किताब की बात कर रहे हैं, जिसमें उनके पत्रकारीय जीवन पर प्रकाश डाला गया है। डॉ. सौरभ मालवीय की किताब 'राष्ट्रवादी पत्रकारिता के शिखर पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी' में अटल जी के पत्रकारीय जीवन के बारे में बखूबी लिखा गया है। इस किताब में अटल जी के जीवन से जुड़ी कई रोचक बातें लिखी गई हैं। किताब की विषय सूची को देखकर ही इसे पढ़ने का मन करता है।

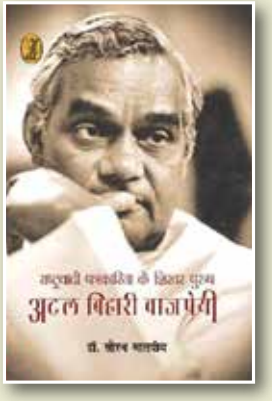

किताब के अनुसार अटल जी मासिक पत्रिका 'राष्ट्रधर्म' के प्रथम संपादक रहे हैं। अटल जी छात्र जीवन से ही संपादक बनना चाहते थे। अटल जी ने पांचजन्य, स्वदेश, वीर अर्जुन और कई अन्य समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए कार्य किया था। 20 जनवरी 1982 में 'तरुण भारत' की रजत जयंती पर अटल जी ने कहा था, 'समाचार पत्र के ऊपर एक बड़ा राष्ट्रीय दायित्व है। भले हम समाचार पत्रों की गणना उद्योग में करें, कर्मचारियों के साथ न्याय करने की दृष्टि से आज यह आवश्यक भी होगा, लेकिन समाचार पत्र केवल उद्योग नहीं है उससे भी कुछ अधिक है।'

लेखक ने अपनी इस किताब में अटल जी के पत्रकारीय सफर का बखूबी वर्णन किया है। अटल जी की एक पत्रकार के रूप में क्या सोच थी और वो देश के विभिन्न मसलों पर क्या सोचते थे, इस बारे में वाणी प्रकाशन से प्रकाशित इस पुस्तक को पढ़कर जाना जा सकता है। ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

दिल्ली स्थित लाल किले पर आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह को संबोधित करते व वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

चाणक्यपुरी (नई दिल्ली) में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया, साथ में केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह

नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना के रजत जयंती कार्यक्रम का शुभारंभ करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और साथ में केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री श्री मनोज सिन्हा व अन्य

रोहतक (हरियाणा) में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को प्रतीकात्मक हल से स्वागत करते हरियाणा भाजपा नेतागण

शिरडी (महाराष्ट्र) में जनाभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सी. विद्यासागर राव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-20

कार्यकर्ताओं एवं शुभचिंतकों से अपील

@AmitShah

भाजपा का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैंने अपनी ओर से 1000 रुपए की राशि पार्टी को दी है। मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं व शुभचिंतकों से अपील करता हूँ कि आप भी 'नरेंद्र मोदी एप' पर जाकर राशि दें और इस अभियान में सहभागी बने। आप http://donations.narendramodi.in से भी यह राशि दे सकते हैं।

As a BJP worker, I have given the party a sum of Rs. 1000. I appeal to all the cadres and well-wishers of the BJP to also go to the 'Narendra Modi app' and become a participant in this campaign. You can also give this amount at http://donation.narendramodi.in

BHARTIYA JANATA PARTY

Central Office

6 A, Pandit Deen Dayal Upadhyaya Marg,New Delhi - 110002

No. 31814 **Date -** 23/10/2018

Received with thanks from Sh./Smt./M/s Amit Shah

Email [redacted] **Mobile** [redacted]

Donated INR 1000 **on** 23/10/2018 01:39:22 pm

Amount INR 1000

Donations to the Party are exempt from Income Tax u/s 80GGB for Companies and u/s 80 GGC for Others as per Income Tax Act, 1961

PAN No.: AAABB0157F **Regn. No.: 56/R/1/89 Dt. 19 Sept. 1989**